छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 209 ■ अम्बिकापुर, बुधवार 12 अगस्त 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

असम में पदस्थ बीएसएफ के जवान 'कमलेश केरकेट्टा' की संदिग्ध मौत

कैंप से लापता होने के बाद मिला शव, गृहग्राम में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई

छ.ग.फ्रंटलाइन

बतौली/अंबिकापुर। असम में सीमा सुरक्षा बल 'बीएसएफ' के 66वीं बटालियन में पदस्थ सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कपाटबाहरी निवासी जवान कमलेश केरकेट्टा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जवान का शव कैंप से लापता होने के बाद बरामद किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ के जवान कमलेश केरकेट्टा, पिता निर्मल केरकेट्टा 36 वर्ष वर्ष 2012-13 से बीएसएफ की 66वीं बटालियन में पदस्थ थे। वर्तमान में वे असम के धुबरी जिले के क्रिस्तापाड़ा क्षेत्र में तैनात थे। बीते गुरुवार रात करीब 12 बजे जवान के कंपनी कैंप से लापता होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद उनकी तलाश शुरू

की गई। जवान की पत्नी ममता केरकेट्टा को कंपनी कमांडर द्वारा शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे फोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। जवान की तलाश लगातार जारी रही। शनिवार रात तक कैंप में वापस नहीं लौटने पर तलाश तेज की गई और शनिवार को रात करीब एक बजे उनका शव बरामद होने की सूचना मिली। जवान की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। घटना को लेकर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार

मंगलवार, 11 अगस्त को बीएसएफ के जवान कमलेश केरकेट्टा का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम कपाटबाहरी पहुंचा। यहां बीएसएफ के अधिकारियों एवं जवानों की उपस्थिति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन, आसपास के लोग तथा बीएसएफ के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

बतौली क्षेत्र में शोक की लहर

कमलेश केरकेट्टा की असम में ड्यूटी के दौरान हुई मौत की खबर से बतौली क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर क्षेत्र के लोगों में कई सवाल उठ रहे हैं और सभी को जांच के निष्कर्ष का इंतजार है।

आयुष्मान पोर्टल की तकनीकी खामी से 'मृतक' के 'स्वस्थ' होने का आया संदेश

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 30 जून को मरीज की मौत और पैकेज लॉक होना स्पष्ट किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनांतर्गत मरीजों के आयुष्मान पैकेज एवं उपचार पूर्ण होने के उपरांत ऑटो जनरेशन के माध्यम से संबंधित मरीज अथवा स्वजन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त होने के संबंध में राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय द्वारा वास्तविक तथ्यों एवं पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

मामला मृत आरक्षक से जुड़ा है, जिसे इलाज के लिए 26 जून को मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान पांचवें दिन, 30 जून को उसकी मौत हो गई थी। वहीं आयुष्मान सारथी पोर्टल से मिले संदेश में मृत आरक्षक को 06 अगस्त को डिस्चार्ज होना और स्वस्थ होकर घर लौटना बताया गया। यह संदेश मोबाइल में स्वजन को मिला, तो वे भौचक रह गए, क्योंकि न सिर्फ वे उसका अंतिम संस्कार कर चुके हैं, बल्कि मृतक का अधिकारिक मृत्यु प्रमाण

उपचार अवधि में 16,700 रुपये का पैकेज हुआ ब्लॉक

मामले में चिकित्सालय प्रबंधन ने प्रशासन के हवाले से जानकारी दी है कि, मरीज स्व. देवनारायण राम पिता मुनेश्वर राम 39 वर्ष, निवासी जशपुर को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अंबिकापुर में 26 जून को शल्य क्रिया विभाग अंतर्गत आईसीयू में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान 30 जून को उनकी मृत्यु हो गई। मरीज की भर्ती अवधि कुल 05 दिवस रही। इस अवधि में उपचार के लिए आईसीयू तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित पैकेज ही ब्लॉक किए गए। इन पैकेजों की कुल व्यय राशि 16,700 रुपये थी। संबंधित मरीज के आयुष्मान कार्ड खाते में 4,74,800 रुपये की राशि शेष है।

क्लेम प्रोसेसिंग में विभिन्न चरणों से गुजरती है प्रक्रिया

बताया गया कि मरीज के उपचार के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्लेम प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में विभिन्न अवसरों पर क्वेरी जनरेट होती है। चिकित्सालय द्वारा मरीज के उपचार से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर क्वेरी के समाधान सहित विभिन्न चरणों में अपडेट किया जाता है। सामान्यत: इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिन का समय लगता है। इसके पश्चात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर क्लेम इनिशिएशन की कार्रवाई नियमानुसार संपादित की जाती है।

पत्र भी जारी हो चुका है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मृत्यु के पूर्व इलाज में आयुष्मान से व्यय हुए पैकेज का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, और डाटा एंट्री जैसी तकनीकी खामियों को इसकी वजह बताया गया है।

डाटा एंट्री में विलंब से 42 दिन बाद हुआ अपडेट

प्रकरण में संबंधित विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा क्लेम की निगरानी में विलंब किया गया। इसके कारण पोर्टल पर क्लेम क्लोज की जानकारी 6 अगस्त 2026 को अपडेट हुई, जो मरीज की मृत्यु के 42 दिन बाद हुई। पोर्टल पर प्रक्रिया अपडेट होने के पश्चात संबंधित मरीज के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑटो जनरेटेड संदेश प्राप्त हुआ। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीज की वास्तविक स्थिति के अनुरूप उपचार से संबंधित पैकेज ही ब्लॉक किए गए थे। इन पैकेजों की कुल राशि 16,700 रुपये थी। मरीज की मृत्यु के समय के पश्चात कोई अतिरिक्त पैकेज ब्लॉक नहीं किया गया।

ऐसे में बायोमेट्रिक एवं ओटीपी प्रक्रिया संभव नहीं

हॉस्पिटल प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मरीज की अनुपस्थिति में आवश्यक प्रक्रिया किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए मरीज के अंगूठे का निशान आवश्यक होता है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी भेजा जाता है। इस संबंध में संपूर्ण विवरण मरीज के आयुष्मान कार्ड से प्राप्त एवं सत्यापित किया जा सकता है।

डिस्चार्ज, रेफरल एवं मृत्यु प्रकरणों में यथास्थिति के अनुरूप संदेश के लिए कार्रवाई

हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जिन मरीजों का आयुष्मान कार्ड ब्लॉक कर उपचार किया जाता है, उनके डिस्चार्ज, रेफरल, मृत्यु आदि प्रकरणों में मरीज की यथास्थिति के अनुरूप ही ऑटो जनरेटेड संदेश भेजे जाने के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए राज्य नोडल एजेंसी, नवा रायपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया है, और प्रकरण संबंधित प्रकाशित समाचार के संदर्भ में वास्तविक तथ्यों एवं पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गई है।

अंबिकापुर-अनूपपुर रेलखंड पर ट्रेनों की लेटलतीफी, 10 घंटे की यात्रा 14 घंटे में

2-3 घंटे विलंब से चल रहीं ट्रेनें, रेल संघर्ष समिति ने स्टेशन प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। अंबिकापुर-अनूपपुर रेलखंड पर प्रतिदिन ट्रेनों के विलंब से परिचालन की गंभीर समस्या को लेकर सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अंबिकापुर मुख्य स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जोन महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने मंडल रेल प्रबंधक से दूरभाष पर भी चर्चा की, जिसमें डीआरएम ने समस्या के निराकरण हेतु सार्थक पहल का आश्वासन दिया है।

जोनल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने बताया कि अंबिकापुर से परिचालित होने वाली ट्रेनें विगत कुछ महीनों से प्रतिदिन 2 से 3 घंटे विलंब से चल रही हैं। नियमित विलंब के कारण यात्रियों की यात्रा का उद्देश्य ही निरर्थक हो रहा है और रेलवे की विश्वसनीयता लगातार घट रही है।

मरीज, छात्र, व्यापारी परेशान-अंबिकापुर से राजधानी रायपुर को जोड़ने वाली अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस 18241/18242 उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रेन है। प्रतिदिन गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु मरीज, विद्यार्थी, व्यापारी और आम नागरिक इस ट्रेन से राजधानी जाते हैं। ट्रेन के विलंब से पहुंचने के कारण अनुसूचित क्षेत्र के गरीब यात्रियों को एक दिन अतिरिक्त रुकना पड़ रहा है, जिससे उनके समय, धन और साधनों पर अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है। सुदूर आदिवासी अंचल से राजधानी तक की यात्रा जो सामान्यत: लगभग 10 घंटे की होनी चाहिए, वह प्राय: 13 से 14 घंटे तक की हो जा रही है।

श्रद्धालुओं को भी हो रही दिक्कत-अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस तथा मेमू ट्रेनें भी निरंतर विलंब से चल रही हैं, जिससे आगे की यात्रा कठिन हो गई है। सावन माह में विलंबित ट्रेनों के कारण उज्जैन सहित अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु कनेक्टिंग नर्मदा एक्सप्रेस की सुविधा से वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने रेल वन सहित विभिन्न ऐप्स में विलंबित गाड़ियों को राइट टाइम दर्शाकर भ्रम फैलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने की मांग की।

पावर रिवर्सल प्रक्रिया में हो सुधार-जेडआरयूसीसी सदस्य मुकेश तिवारी ने सुझाव दिया कि अनूपपुर और शहडोल में अतिरिक्त पावर की व्यवस्था कर पावर रिवर्सल प्रक्रिया में सुधार किया जाए तो डिटेंशन में 30-40 मिनट की कमी की जा सकती है। बिलासपुर से अनूपपुर के बीच तीसरी लाइन बनने के बाद भी कोचिंग ट्रेनों की समय-सारिणी में सुधार नहीं होना चिंता का विषय है। लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों के कारण यात्री गाड़ियों की स्थिति और दयनीय हो रही है।

बिलासपुर डिवीजन 68वें स्थान-मुकेश तिवारी ने कहा कि हमारे जोन का बिलासपुर डिवीजन मात्र 43.42 प्रतिशत पंक्चुअलिटी के साथ 68वें स्थान पर है। समिति ने ट्रेनों का समय पालन सुनिश्चित करने और विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मिश्रा, नकुल सोनकर, जितेंद्र सिंह, विनोद जायसवाल उपस्थित रहे।

'आदिवासी समाज का अघोषित बहिष्कार कर रही भाजपा'-डॉ. प्रेमसाय सिंह

विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार की चुप्पी पर कांग्रेस का हमला

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रदेश सरकार द्वारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अघोषित बहिष्कार और उपेक्षा के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के 15 आदिवासी समुदाय बहुल जिलों में कांग्रेस ने एक साथ प्रेसवार्ता कर सरकार पर तीखा हमला बोला।

राजीव भवन अंबिकापुर में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार की ओर से कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। प्रदेश की राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री जो स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, उनके द्वारा एक बधाई संदेश तक जारी नहीं

किया गया। उन्होंने इसे देश और प्रदेश के आदिवासी समुदाय की घोर उपेक्षा बताते हुए कहा कि इसे भाजपा द्वारा सर्व आदिवासी समाज के अघोषित बहिष्कार के तुल्य माना जाना चाहिए। डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि 'संघ परिवार और भाजपा हमें आदिवासी के रूप में स्वीकार ही नहीं करती, वो तो हमें वनवासी कहती है'। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की कल्याणकारी नीतियों के परिणामस्वरूप आज आदिवासी समाज के लोग शिक्षित होकर देश के विकास में अन्य समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री सहित बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री और विधायक इस सरकार में मौजूद हैं, लेकिन ये सभी आदिवासी दिवस पर अपने समुदाय की उपेक्षा पर चुप हैं। 'वे किसके दबाव में हैं, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए'। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समुदाय की महान विरासत को चौक-चौराहे पर मूर्तियों में कैद कर आदिवासियों के वोटबैंक के लिए 'टोकनिज्म की राजनीति' करती है। एक ओर भाजपा हमें वनवासी कहती है वहीं पूरे प्रदेश में हमारे वन के साथ ही कृषि भूमि को अपने खास उद्योगपति को परोसकर हमें संसाधन विहीन कर रही है।

जिलाध्यक्ष ने जताई नाराजगी

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग की 14 सीटों सहित बस्तर, कोरबा जैसे जिलों से प्राप्त आदिवासी समुदाय के समर्थन से उन्होंने यह सरकार बनाई है। 2023 के पहले हरेक विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई देने वाली भाजपा, सरकार बनाने के बाद इतनी वैचारिक दरिद्र हो गई है कि 32 प्रतिशत की बड़ी आबादी वाले सर्व आदिवासी समाज के लिए एक सार्वजनिक आयोजन करना तो दूर, एक बधाई संदेश भी जारी करना उचित नहीं समझा।

आदिवासी कांग्रेस का आरोप

आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल पैकरा ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए भी आदिवासी दिवस की उपेक्षा संघ परिवार के दबाव का परिणाम है। देश-प्रदेश में भाजपा की सरकार आदिवासियों के आरक्षण के हित को भी समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रेसवार्ता के दौरान मो. इस्लाम, इंद्रजीत सिंह धंजल, राशिद अहमद, लोकेश कुमार, जमील खान, आलोक सिंह, गुरुप्रीत सिद्धू, नरेंद्र विश्वकर्मा, दिनेश शर्मा, रजनीश सिंह, अमित सिंह मौजूद रहे।

नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर आक्रामक हुईं महापौर, सदन में मचा हंगामा

ऑडियो प्रकरण पर नहीं मिला जवाब, विपक्ष ने किया सामान्य सभा का बहिष्कार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। महापौर मंजूषा भगत के कथित आडियो प्रकरण को लेकर मंगलवार, 11 अगस्त को नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष द्वारा जवाब मांगे जाने पर महापौर का आक्रामक रुख सामने आया। सत्ता पक्ष के लोग मेज पीटते रहे, इन सबके बीच हंगामा की स्थिति बनती रही और विपक्षी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सामान्य सभा की कार्रवाई बिना विपक्ष के ही चलती रही।

राजमोहिनी देवी भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक में पहले 8 नये मनोनीत पार्षदों का स्वागत किया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने महापौर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष के कथित ऑडियो वायरल होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा आश्चर्य की बात है कि, जिस मामले में स्वयं महापौर ने थाने में शिकायत की है, उसमें पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एसपी को भेजने और महापौर से सदन में जवाब देने की मांग की। इस पर एमआईसी प्रभारी मनीष सिंह ने पहले प्रश्नोत्तर काल चलाने की बात कही। विपक्ष ने इसे आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए पहले जवाब देने की मांग शुरू कर दी। बैठक में महिला बाल विकास विभाग से कुसुम जायसवाल, खाद्य विभाग से जिला खाद्य अधिकारी शिवेन्द्र कामटे और पुलिस विभाग से एएसपी रितेश चौधरी को बुलाया गया था। सदन में हंगामे को देखकर अधिकारी भी चुप्पी साधे रहे।

महापौर हुईं आक्रामक, स्थगित हुई कार्रवाई

विपक्ष के दबाव पर महापौर मंजूषा भगत जवाब देने खड़ी हुईं। बार-बार एक ही मुद्दा उठाए जाने पर उन्होंने विपक्ष पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस दौरान महापौर का स्वर काफी तेज हो गया और वे आक्रामक होकर बोलने लगीं। उन्होंने निगम में कांग्रेस शासन के समय भेदभाव के आरोप भी लगाए। महापौर के बोलने के तरीके पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। पक्ष-विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। डेढ़ बजे सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

बहिष्कार कर निकले विपक्षी पार्षद

पुन: कार्रवाई शुरू होने पर विपक्ष ने फिर जवाब मांगा। सत्ता पक्ष के हस्तक्षेप के बाद विपक्षी पार्षदों ने सामान्य सभा का बहिष्कार कर सदन से बाहर निकल गए। एमआईसी सदस्य मनीष सिंह और पार्षद आलोक दुबे ने मान-मनौव्वल की, लेकिन विपक्षी पार्षद नहीं माने। नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने महापौर के आचरण को संसदीय परंपरा के विरुद्ध बताया। विपक्ष के जाने के बाद निगम में उपस्थित अधिकारियों से केवल सत्ता पक्ष के पार्षदों ने ही सवाल किए और कार्रवाई पूरी हुई।

राज्य स्तरीय गतका प्रतियोगिता में सरगुजा के खिलाड़ियों ने जीते 35 पदक

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। माता सुंदरी पब्लिक स्कूल, रायपुर में आयोजित तृतीय सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर गतका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता-2026 में द गतका एसोसिएशन ऑफ सरगुजा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता द गतका एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वावधान एवं गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया की संबद्धता में आयोजित की गई थी। सरगुजा जिले के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्ग एवं विधाओं में कुल 35 पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। द गतका एसोसिएशन ऑफ सरगुजा के पदाधिकारी बलविंदर सिंह छाबड़ा ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरगुजा जिले में गतका खेल का और अधिक विस्तार किया जाएगा। जिले के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सरगुजा के खिलाड़ी इसी तरह राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करते रहें। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को खिलाड़ियों एसोसिएशन के पदाधिकारियों, दशमेश पब्लिक स्कूल परिवार एवं अन्य खेलप्रेमियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सरगुजा जिले की टीम का नेतृत्व राजेश प्रताप सिंह, रजत सिंह, कृष्ण एक्का, आकाश कश्यप एवं प्रिया जायसवाल ने किया।

80 खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन-राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरगुजा जिले से कुल 80 खिलाड़ियों ने विभिन्न विधाओं में भाग लिया। खिलाड़ियों ने टीम सोटी एवं टीम फरी सोटी के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि गतका खेल के प्रचार-प्रसार एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दशमेश स्कूल परिवार ने विशेष सहयोग प्रदान किया।

के आर टेक्निकल कॉलेज
SINCE 2008
(Regular | Private | Distance)
ADMISSION OPEN 2026-27
मान्यताएँ
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से सम्बद्ध
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त
इग्नू का स्टडी सेंटर
SINCE 2008
COURSES OFFERED
UG COURSES: BCA, BBA, BCOM, BSC BIO, BSC MATHS, BSC CS, BA
PG COURSES: MSC CS, MSC IT, MSC BOTANY, MSC ZOOLOGY, MSC CHEMISTRY, MSC MATHS, MSC PHYSICS, MCOM, MSW, MA HINDI
PROFESSIONAL COURSES: DCA, PGDCA, PGDBM, PGDRD, BLIB
SCHOLARSHIP FACILITIES
विद्यासागर छात्रवृत्ति (सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए)
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC, ST एवं OBC विद्यार्थियों हेतु)
सीमित कोर्स में फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध
COLLEGE CAMPUS: अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन के पास, काली घाट मंदिर के आगे, संजय नगर, छत्तीसगढ़
9926513170, 9826612781
CITY OFFICE: कृष्ण आभा भवन, रिंग रोड, नमना कला, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़
9826183771

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026
ISO 9001: 2015 CERTIFIED
बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।
डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद
समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा
बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

वेतन समझौते में देरी पर कोयला कर्मचारियों के संयुक्त ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

विश्रामपुर। कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत लाखों गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण को लेकर श्रमिक संगठनों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। 11 वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी 12 वें वेतन समझौते के लिए संयुक्त द्विपक्षीय कोयला उद्योग समिति की वार्ता समिति का गठन नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को संयुक्त ट्रेड यूनियनों एटक, एचएमएस, सीटू और इंटक के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया गया।प्रदर्शन के दौरान श्रमिक नेताओं ने कोल इंडिया प्रबंधन और केंद्रीय कोयला मंत्रालय पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द ही 12 वें वेतन समझौते के लिए वार्ता समिति का गठन नहीं किया गया और लंबित मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जा सकता है। सभा को संबोधित करते हुए श्रमिक नेताओं ने कहा कि 11 वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है। वहीं 12 वें वेतन समझौते की अवधि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होनी है। बावजूद इसके अभी तक नई वार्ता समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इस स्थिति ने कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत लगभग 2.25 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के बीच असमंजस, निराशा और आक्रोश की स्थिति पैदा कर दी है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि वेतन समझौता केवल वेतन बढ़ोतरी का विषय नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, सुविधाओं और सेवा शर्तों से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है। ऐसे में वार्ता प्रक्रिया शुरू करने में हो रही देरी कर्मचारियों के हितों के साथ गंभीर खिलवाड़ है। संयुक्त मोर्चे ने केवल 12 वें वेतन समझौते के लिए वार्ता समिति गठित करने की मांग ही नहीं की, बल्कि 11 वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते में तय किए गए शेष लंबित मुद्दों का भी तत्काल क्रियान्वयन किए जाने की मांग उठाई। श्रमिक नेताओं ने कहा कि जब 11वें वेतन समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी है, तब उसके अंतर्गत तय किए गए लंबित प्रावधानों को लागू करने में किसी तरह की टालमटोल उचित नहीं है। कर्मचारियों के हित में प्रबंधन को लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करना चाहिए। सभा में आंदोलन के मुख्य वक्ता एटक से पंकज कुमार गर्ग, एचएमएस से रामाशीष पाल, सीटू से सुरेश पटेल तथा इंटक से अजीत यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि कोयला कर्मचारी देश की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ हैं। विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए ये कर्मचारी देश के बिजलीघरों और उद्योगों को ऊर्जा का आधार प्रदान करते हैं। इसके बावजूद उन्हीं कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण को लेकर सरकार और प्रबंधन की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि 12 वें वेतन समझौते की प्रक्रिया को लंबा खींचने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। यदि समय रहते केंद्र सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो आने वाले दिनों में श्रमिक संगठन संयुक्त रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे। सभा को विभिन्न श्रम संगठनों से जुड़े हीरालाल, सजल मित्रा, आरके द्विवेदी, कामदेव सिंह, जया कुमारी, अरविंद सिंह, अप्पा राव एवं शिवाकांत मिश्रा सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में 12 वें वेतन समझौते की वार्ता समिति का तत्काल गठन करने की मांग दोहराई। संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह मामले को गंभीरता से लेते हुए कोल इंडिया प्रबंधन को आवश्यक निर्देश जारी करे और 12 वें वेतन समझौते के लिए संयुक्त द्विपक्षीय कोयला उद्योग समिति की वार्ता समिति का अविलंब गठन सुनिश्चित करे। श्रमिक नेताओं ने चेताया कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो कोयला कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कोल इंडिया प्रबंधन एवं कोयला मंत्रालय की होगी। विरोध प्रदर्शन एवं सभा पश्चात संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एसकेपी शिंदे एवं सुरक्षा प्रभारी रात्रे को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से 12वें वेतन समझौते के लिए नई वार्ता समिति के गठन में हो रही देरी की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कराया गया। साथ ही मांग की गई कि बिना किसी और विलंब के वार्ता समिति का गठन कर वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाए तथा 11वें वेतन समझौते के शेष लंबित मुद्दों का भी तत्काल निराकरण किया जाए। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र नागपुरे ने किया।

12 वें वेतन समझौते के लिए तत्काल वार्ता समिति गठित करने की मांग

पत्नी को धमकी दे खिलाया गर्भनिरोधक गोली, जुर्म दर्ज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

विश्रामपुर। गर्भवती पत्नी को गर्भनिरोधक गोली खिलाने मामले में पत्नी की शिकायत पर लटोरी पुलिस ने पति ग्राम करवां निवासी सूरजभान कुशवाहा के खिलाफ बीएनएस की धारा 89, 351(2) के तहत जुर्म दर्ज किया है। लटोरी पुलिस ने बताया कि घटना पांच दिन पुरानी है। आरोपी पति सूरजभान कुशवाहा को उसकी पत्नी ने बताया कि वह गर्भवती है, जिसके बाद उसके पति ने यह कहते हुए कि उसे बच्चा नहीं चाहिए और उसके मुंह में जबरन गर्भनिरोधक गोली डाल दिया।पत्नी के मुताबिक पति ने उसे धमकाया भी था। गोली खाने के बाद उसकी तबियत बिगड़ गई। इसके बाद उसने अस्पताल जाकर अपना उपचार कराया और फिर पति के खिलाफ उसने जुर्म दर्ज कराया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में उसका विवाह हुआ है और उसका यह पहला बच्चा था लेकिन उसके पति को जब उसने अपने गर्भवती होने की बात बताई तो पति नाराज होकर उसे बच्चा नहीं चाहिए कह जबरन गोली खिला दिया।फिलहाल पुलिस जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ट्राई बेकर में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बतरा की टीम ने जीता मैच

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

विश्रामपुर। एकता स्टेडियम में आयोजित न्यू टैलेंट प्रोत्साहन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बतरा और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लटोरी के बीच खेला गया। जिसमें हाफ टाइम तक दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर रही। फुल टाइम में दोनों टीम में एक-एक से बराबर रहे। दोनों टीम ट्राई बेकर में बतरा की टीम ने 9-8 से मैच जीत लिया। मैच का मैन ऑफ द मैच बतरा के विवेक रहे। आज मुख्य अतिथि के रूप में अशोक गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच की शुरुआत की घोषणा किया। दूसरे मैच के मुख्य अतिथि जाकेश राजवाड़े थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र पासवान थे। टूर्नामेंट के आयोजक व जिला सूरजपुर डयूज बाल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेश जैन ने बताया कि स्पर्धा का फाइनल मैच 15 अगस्त को खेला जाएगा।

प्राचार्य के विरुद्ध हाईस्कूल सिलफिली के छात्र छात्राओं ने गेट बंदकर किया प्रदर्शन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

विश्रामपुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली के प्राचार्य पर स्कूल स्टॉफ से अभद्रता एवं छात्राओं से अश्लील हरकत करने की शिकायत को लेकर मंगलवार दोपहर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य के विरुद्ध मोर्चा खोल स्कूल के प्रवेश द्वार में ताला जड़कर प्राचार्य के खिलाफ कार्यवाही और उन्हें विद्यालय से पृथक करने की मांग को लेकर घंटों प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर लटोरी तहसीलदार चंद्रशिला जायसवाल, सुरजपुर बीईओ हरेंद्र सिंह सहित जयनगर पुलिस मौके पर पहुंच स्कूली बच्चों से बात कर उनका पक्ष जाना। बताया जा रहा है कि तहसीलदार सहित बीईओ ने प्राचार्य सहित स्कूली शिक्षकों से भी उनका पक्ष जानने बयान लिया जिसमें बच्चों की शिकायत सही मिली है।

जिसके बाद प्राचार्य के खिलाफ पखवाड़े भर के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही का बच्चों को आश्वासन दिया गया है। साथ ही तात्कालिक रूप से प्राचार्य को संस्था से पृथक रखने, विभागीय स्तर पर व्यवस्था किए जाने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद दो ढाई घंटे के आंदोलन स्कूली बच्चों ने समाप्त कर दिया है। प्राचार्य आईडी खलखो पर आरोप है कि विद्यालय की महिला कर्मी के घर में अकेले रहने के बाबजूद उसके घर में प्रवेश करने की कोशिश की गई। साथ ही महिला कर्मी से एक लाख रुपए की मांग करते हुए उसके ऊपर दबाव बनाने और यह कहना कि उसे जिला शिक्षा अधिकारी बनना है, पैसे की आवश्यकता है वह पैसा जमा कर रहा है अगर वह पैसा नहीं देगी तो उसे वह परेशान कर देगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय में शराब पीकर पहुंचने, विद्यालय के कर्मियों से अभद्र व्यवहार सहित छात्र छात्राओं से अश्लील व्यवहार के आरोप लगे हैं। फिलहाल लटोरी तहसीलदार और सुरजपुर बीईओ की जांच में मामला सही पाए जाने के बाद प्राचार्य को फिलहाल पखवाड़े भर के लिए अवकाश पर भेजकर विद्यालय की शिक्षिका निर्मला ज्योति को प्राचार्य का प्रभार दिलाया गया है। अग्रिम जांच कार्यवाही उपरांत उचित कार्यवाही का भरोसा अधिकारियों द्वारा दिया गया है।

हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत तिरंगे की शान में एकजुट हुआ जिला

★ हाथों में तिरंगा देश भक्ति के जोश के साथ निकाली गई तिरंगा रैली

★ अभियान में गांव की गलियों से नगर के चौराहों तक दिखा देश भक्ति का उत्साह

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। हाथों में तिरंगा, चेहरे पर गर्व और कदमों में देशभक्ति का जोश। लहराता तिरंगा, वंदे मातरम के नारे और देशभक्ति गीतों की धुन पर पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रही तिरंगा रैली ने विकासखंड राजपुर मुख्यालय में पूरे वातावरण को राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग दिया।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकली तिरंगा रैली हाई स्कूल ग्राउंड से निकल कर गांधी चौक मुख्य मार्ग से होते हुए वापस हाई स्कूल पहुंची जहां करीब 6 किलोमीटर तक निकली इस रैली में स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 1000 से अधिक लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले। रैली में लहराते तिरंगे और गूंजते वंदे मातरम के नारों ने राजपुर की सड़कों पर ऐसा उत्साह पैदा किया कि राहगीर भी इस देशभक्ति के कारवां से जुड़ते नजर आए।

तिरंगा थाम विधायक भी बनीं देशभक्ति के कारवां का हिस्सा

हर घर तिरंगा अभियान के तहत विकासखंड राजपुर में निकली भव्य तिरंगा रैली में सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने सहभागिता कर राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। हाथों में तिरंगा लेकर उन्होंने रैली में शामिल स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाया।

रैली में शामिल बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे जब पूरे जोश के साथ देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े, और आमजन भी उसी उत्साह में शामिल हो गए। देशभक्ति गीतों से गूंजता वातावरण स्वतंत्रता दिवस से पहले ही राजपुर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। रैली में एकता और राष्ट्रप्रेम में जुड़ते लोग जिसमें उम्र, पद और वर्ग की सीमाएं पीछे छूट गईं और जहां सबकी पहचान सिर्फ भारत के नागरिक के रूप में नजर आए।

हर घर तिरंगा अभियान से जन-जन जुड़ने की अपील

सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और देश के प्रति अपने सम्मान एवं गर्व को व्यक्त करें।हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव से जुड़ने का अवसर है। उन्होंने अपील किया है कि जन-जन इस अभियान में उत्साहपूर्वक सहभागी बनें और स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाएं।

गांव की गलियों से गूंजा राष्ट्रप्रेम का संदेश

जनपद पंचायत वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत शारदापुर सहित विभिन्न ग्रामपंचायतों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकली तिरंगा यात्रा ने पूरे गांव को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लेकर ग्रामीणों ने गांव की गलियों में भ्रमण करते हुए हर घर तक राष्ट्रध्वज और राष्ट्रप्रेम का संदेश पहुंचाया। यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह एवं गौरव के साथ मनाने के लिए प्रेरित किया गया।

सदस्यता सत्यापन को लेकर क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति की हुई बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

विश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को आयोजित क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति आरजेसीसी की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सदस्यता सत्यापन की तिथियों से लेकर कर्मचारियों के सत्यापन स्थल, बीमार एवं अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों तथा विभिन्न खदानों व सहक्षेत्र कार्यालयों में सत्यापन की व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई।

बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद अब सदस्यता सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों और यूनियनों के बीच बनी असमंजस की स्थिति काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। प्रबंधन द्वारा बैठक की कार्यवाही का मिनट जल्द जारी किए जाने के बाद प्रत्येक यूनिट में बैठक आयोजित कर सत्यापन का समय और संबंधित खदान अथवा कार्यस्थल निर्धारित किया जाएगा।बैठक में तय किया गया कि सदस्यता सत्यापन के लिए 10, 11 एवं 19 सितंबर की तिथियां निर्धारित की गई हैं। इनमें 19 सितंबर की तारीख

विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए रखी गई है, जो 10 एवं 11 सितंबर को स्वीकृत अवकाश पर रहेंगे या बीमारी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित होंगे। बैठक में अस्थाई कर्मचारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तय किया गया कि अस्थाई कर्मचारियों का सदस्यता सत्यापन उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही किया जाएगा। इससे ऐसे कर्मचारियों को सत्यापन के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाने की परेशानी नहीं होगी। बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय एकल सदस्यता वाले कर्मचारियों से संबंधित रहा। यदि किसी कर्मचारी की सदस्यता केवल एक यूनियन में है और इसको लेकर कोई आपत्ति दर्ज होती है, तो उसका सत्यापन केवल नोटा के रूप में किया जाएगा।

यह निर्णय सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुम्दा सहक्षेत्र के कर्मचारियों का सदस्यता सत्यापन केवल सहक्षेत्र कार्यालय में एक ही स्थान पर किया जाएगा। इससे अलग-अलग इकाइयों में सत्यापन को लेकर होने वाली असुविधा और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। इसी तरह आरजीके सहक्षेत्र कार्यालय एवं रेहर खदान के कर्मचारियों का सदस्यता सत्यापन भी एक ही स्थान पर किया जाएगा। इसके लिए रेहर को सत्यापन केंद्र निर्धारित किया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि गायत्री एवं केतकी खदानों के कर्मचारियों का सदस्यता सत्यापन उनकी संबंधित खदानों में ही कराया जाएगा। इससे कर्मचारियों को दूर स्थित किसी अन्य सत्यापन केंद्र तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में यह भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 10 एवं 11 सितंबर को बीमारी की छुट्टी या स्वीकृत अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों, जिनका सदस्यता सत्यापन 19 सितंबर को किया जाना है, उनकी सूची 13 सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस व्यवस्था से 19 सितंबर को होने वाले सत्यापन के लिए पात्र कर्मचारियों की पहचान पहले ही स्पष्ट हो जाएगी और अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी की संभावना कम होगी। बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का प्रबंधन द्वारा जल्द से जल्द आधिकारिक मिनट जारी किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक यूनिट में बैठक आयोजित की जाएगी। इन्हीं बैठकों में सदस्यता सत्यापन का समय और संबंधित खदान अथवा कार्यस्थल यूनिट जेसीसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

सागौन लकड़ी चोरी रोकने पर वन रक्षक पर जानलेवा हमला, पति-पत्नी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बलरामपुर। जिले के रामानुजगंज जंगल में लकड़ी चोरी कर ले जा रहे पति-पत्नी को रोकना वन रक्षक को भारी पड़ गया। आरोप है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने वन रक्षक के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और सिर पर रखें सागौन का लट्ठा उसके ऊपर पटककर हमला कर दिया। हमले में वन रक्षक के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में रामानुजगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सुबह रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक पिंटू मालाकार ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान वन वाटिका के पास उन्हें एक महिला और पुरुष जंगल की ओर से सागौन का लकड़ी लेकर आते दिखाई दिए। वन

रक्षक ने दोनों को रोककर पूछताछ की। आरोप है कि पूछताछ से नाराज होकर मनोज भुईया उम्र 32 और उसकी पत्नी मानमती भुईया 30 निवासी वार्ड क्रमांक 15 रामानुजगंज, ने वन रक्षक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। दोनों ने रास्ते से हट जाने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान सिर पर रखा सागौन का लट्ठा वन रक्षक के ऊपर पटक दिया गया और दोनों ने उसके साथ मारपीट की। हमले में पिंटू मालाकार के सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी की रिपोर्ट पर थाना रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 140/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं 296, 115(2), 351(2), 121(2), 132 एवं 3(5) में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया है।

मिनी माता की पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने अर्पित की श्रद्धांजलि

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बलरामपुर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मंगलवार को जिला ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अविभाजित मध्यप्रदेश की प्रथम महिला सांसद एवं छत्तीसगढ़ की महान समाज सुधारक मां मिनी माता जी की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसजनों ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को स्मरण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य समीर सिंह देव ने कहा कि मिनी माता ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के कमजोर वर्गों के अधिकार और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक समानता तथा महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रशांत विश्वास, कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला सचिव बुद्धदेव पोया, राजा चौबे, कृपा शंकर, विनोद मेहता, कर्मदयाल रक्सेल, जय राम सिंह, राजेश गुप्ता, उमा गुप्ता, बाशदेव, अर्जुन सोनवानी, बिछान राम, इफराज अली, विनोद मिंज, वाशिम खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सीमा पर ढिलाई, बिना दस्तावेज वाहनों से राजस्व और सुरक्षा दोनों को खतरा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रघुनाथनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत सीमावर्ती रघुनाथनगर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से आने-जाने वाले वाहनों की अवैध आवाजाही को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में कई मैजिक, टेंपो, बस और ऑटो बिना वैध परमिट और जरूरी दस्तावेजों के लगातार संचालित हो रहे हैं।

जांच व्यवस्था पर उठे सवाल

रघुनाथनगर क्षेत्र यूपी सीमा से सटा होने के कारण यहां वाहनों की नियमित जांच जरूरी मानी जाती है। लेकिन नागरिकों का कहना है कि बिना परमिट वाहनों के खुलेआम चलने से परिवहन विभाग की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।स्थानीय लोगों ने यह भी आशंका जताई कि कुछ वाहनों के जरिए यूपी से शराब और अन्य सामान लाया जा रहा है।हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही संभव है।लोगों ने प्रशासन से सीमावर्ती मार्गों पर सघन जांच अभियान चलाने की मांग की है।

क्या हो रही है नियमों की अनदेखी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि बिना परमिट और दस्तावेजों के वाहन दौड़ रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या नियमित जांच हो रही है? सीमावर्ती मार्गों पर परिवहन विभाग की निगरानी कितनी मजबूत है? इन सवालों का जवाब अब प्रशासन की कार्रवाई से ही मिलेगा।

राजस्व और सुरक्षा दोनों पर खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि बिना दस्तावेज वाले वाहनों का संचालन सिर्फ परिवहन नियमों का उल्लंघन नहीं है।यदि इनसे अवैध शराब या प्रतिबंधित सामान पकड़ा जाता है तो यह राजस्व नुकसान के साथ-साथ कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकता है।

संयुक्त जांच की उठी मांग

क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रघुनाथनगर और सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवहन विभाग, आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर विशेष जांच अभियान चलाया जाए।वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, टैक्स सहित सभी कागजातों की जांच कर नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

उठ रहे 4 बड़े सवाल

बिना परमिट वाहन कैसे चल रहे? सीमावर्ती क्षेत्र में इनकी निगरानी कौन कर रहा है?

जांच सिर्फ खानापूर्ति? नियमित जांच न होने से नियम तोड़ने वालों के हौसले बढ़े।

अवैध सामान कौन रोकेगा? यूपी से शराब/अन्य सामान आने की आशंका, जांच जरूरी।

संयुक्त अभियान कब? परिवहन और आबकारी विभाग ने आखिरी बार साथ में कब कार्रवाई की?

अब देखना होगा कि क्षेत्रवासियों की शिकायतों पर प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध वाहन संचालन पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

जर्जर सड़क पर धान का रोपा लगाकर वार्डवासियों ने जताया विरोध

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12 में सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान वार्डवासियों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया।लंबे समय से कीचड़युक्त और जर्जर सड़क से आवागमन करने को मजबूर लोगों ने सड़क पर ही धान का रोपा लगाकर जिम्मेदारों का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित किया। यह विरोध प्रदर्शन राजेश जगते के नेतृत्व में किया गया। वार्डवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है।जगह-जगह गड्ढों और कीचड़ के कारण पैदल चलना तो दूर, दोपहिया और चारपहिया वाहनों से आवागमन भी मुश्किल हो गया है।स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने कहा कि कई बार सड़क की समस्या की ओर जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ।

आधार की गलती बनी बाधा, सेवा सेतु ने पल में किया समाधान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। सेवा सेतु केंद्र नागरिकों की छोटी-बड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान में मददगार साबित हो रहा है। इसी कड़ी में अम्बिकापुर की डॉली गंधर की आधार कार्ड में नाम संबंधी त्रुटि को सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से ठीक किया गया। डॉली के आधार कार्ड में नाम गलत होने के कारण उनका बैंक खाता नहीं खुल पा रहा था। खाता न होने की वजह से उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। डॉली ने सेवा सेतु केंद्र में आवेदन दिया। आवेदन के आधार पर प्रक्रिया पूरी कर उनके आधार कार्ड में नाम की त्रुटि सुधार दी गई। अब नाम सही होने से बैंक खाता खुलवाना और छात्रवृत्ति प्राप्त करना आसान हो गया है। डॉली ने कहा, ₹आधार में गलती की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। सेवा सेतु केंद्र में आवेदन के बाद समस्या हल हो गई। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार। सेवा सेतु केंद्र के जरिए नागरिकों को आधार, बैंकिंग, छात्रवृत्ति सहित अन्य शासकीय सेवाओं से जुड़ी दस्तावेज संबंधी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर मिल रहा है। शासन का उद्देश्य है कि दस्तावेजों की त्रुटि के कारण कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

विभाजन पीड़ितों का होगा सम्मान, दिवंगत आत्माओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि

कुरुक्षेत्र। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर 14 अगस्त को पंचायत भवन , कुरुक्षेत्र में 'सम्मान एवं श्रद्धांजलि सभा' का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विभाजन के दौरान विस्थापन की पीड़ा झेलने वाले उन बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा, जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही विभाजन की त्रासदी में अपने प्राण गंवाने वाले तथा दिवंगत हो चुके विभाजन पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। यह कार्यकर्म पंजाबी बिरादरी महासभा कुरुक्षेत्र द्वारा किया जाएगा कार्यकर्म के संयोजको आशीष बल्कि लाखों परिवारों की पीड़ा, संघर्ष और त्याग की जीवंत स्मृति है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबल, उन्नत मक्का बीज से बढ़ेगी शुभम दुबे की आय

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। किसानों की आय बढ़ाने और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन अब जमीन पर असर दिखा रहा है। योजना के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम कृष्णापुर के कृषक शुभम दुबे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।उन्होंने करीब 2 एकड़ जमीन में मक्का की खेती की है।शुभम ने बताया कि कृषि विभाग से उन्हें उन्नत किस्म का मक्का बीज और खाद मिला। बीज की अच्छी गुणवत्ता के कारण पौधों की बढ़वार बेहतर हुई। विभाग के सुझाव पर खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का उपयोग करने से फसल को साफ-सुथरा माहौल मिला और उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। शुभम पहले सब्जी की खेती करते थे, लेकिन उससे अपेक्षित आय नहीं मिल पाती थी। मक्का की खेती से अब उन्हें उत्पादन के साथ-साथ बेहतर आय की उम्मीद है। फसल जल्दी तैयार होने से उन्हें बाजार में सही समय पर बेचने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा, ₹कृषि विभाग के सहयोग से फसल अच्छी हो रही है। मक्का की खेती से मेरी आय बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।₹ उन्होंने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कृषि विभाग का आभार जताया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी जानकारी देकर फसल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। शुभम दुबे की मक्का फसल इसका उदाहरण है जहां सही बीज, पोषण और खरपतवार नियंत्रण से फसल मजबूत हुई है और किसान की आय बढ़ने का रास्ता खुला है।

मोहरसोप में कक्षा 9वीं की छात्राओं को मिली सरस्वती साइकिल, चेहरे पर दिखी खुशी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

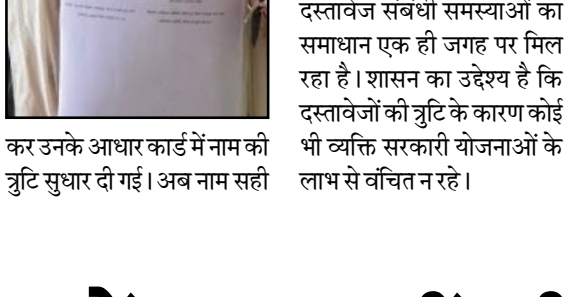

चांदनी बिहारपुर। क्षेत्र के शा. उ. मा. विद्यालय मोहरसोप में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासन की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना तथा बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर उनकी नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान पात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। साइकिल मिलने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। छात्राओं ने शासन की इस योजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि साइकिल मिलने से विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी और समय की भी बचत होगी। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के उपसरपंच प्रेमलाल विश्वकर्मा उपस्थित रहे। इसके अलावा बिहारपुर मंडल में नीति एवं अनुसंधान प्रमुख तथा बूथ मोहरसोप के युवा प्रभारी धर्मेंद्र तिवारी ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने छात्राओं को साइकिल प्रदान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के संस्था प्रमुख एवं प्राचार्य महेश कुमार भगत सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से शासन की सरस्वती साइकिल योजना को छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं के लिए आवागमन की सुविधा शिक्षा की निरंतरता में अहम भूमिका निभाती है। साइकिल मिलने से छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा मिल रही है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना तथा शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना है। मोहरसोप में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम भी इसी दिशा में शासन की पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

प्रेमनगर में गूंजा देशभक्ति का जज्बा, विधायक के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्वह्नहर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगाह्नअभियान के तहत मंगलवार को जनपद मुख्यालय प्रेमनगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक भूलन सिंह मरावी की उपस्थिति में आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता एवं कार्यकताओं सहित आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र ह्नभारत माता की जयह्न, ह्नवंदे मातरम्ह्न और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लेकर निकले बच्चों, युवाओं और नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशप्रेम का संदेश दिया। यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए जनपद मुख्यालय तक पहुंची, जहां लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ तिरंगे का सम्मान किया। प्रेमनगर विकासखंड में बिरेची बाबा से गणेश पंडाल तक भव्य एवं सौहार्दपूर्ण तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य ह्नदेश की आन, बान और शान तिरंगा तथा हर घर तिरंगाह्न अभियान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना रहा। यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे, ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

देशभक्ति के रंग में रंगा रामानुजनगर, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे छात्र

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत सोमवार को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राचार्य के मार्गदर्शन में भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर आमजन में राष्ट्रप्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना जागृत की। प्राचार्य पी. सी. सोनी के नेतृत्व एवं समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के सहयोग से विद्यालय की कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। सभी विद्यार्थी विद्यालय की ड्रेस में अनुशासित होकर कतारबद्ध निकले। तिरंगा यात्रा विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर सुभाष चौक होते हुए बस स्टैंड मार्ग से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान बच्चों द्वारा 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'तिरंगे की शान में' जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। राहगीर भी बच्चों का उत्साह देखकर रुककर तिरंगे को नमन करते नजर आए। तिरंगा यात्रा के पश्चात विद्यालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाया। इसके बाद शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बच्चों को देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य पी. सी. सोनी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ₹तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है।₹ उन्होंने सभी से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया।

पीएम श्री सेजस रामानुजनगर में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने शशिनाथ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल रामानुजनगर में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया। विद्यालय में आयोजित बैठक के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 24 सदस्यीय शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष पद पर शशिनाथ तिवारी को नियुक्त किया गया। शाला प्रबंधन समिति के गठन का उद्देश्य विद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विकास में अभिभावकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। समिति विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की सुविधाओं, अनुशासन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समिति के गठन के दौरान विद्यालय के विकास एवं विद्यार्थियों के हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने नवगठित समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर सरपंच रामसिंह, उपसरपंच दशरथ गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा कपिल पाण्डेय, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, महामंत्री सौभाग्य दुबे, रिशी दुबे, शिवदयाल सिंह, प्राचार्य पीसी सोनी, दिलीप शर्मा, नरेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नवगठित शाला प्रबंधन समिति से विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों के हित में बेहतर वातावरण तैयार करने की उम्मीद जताई गई है।

नाम सुधार प्रकाशन हेतु ईश्तहार

मैं वंशलाल, पिता भानमती, जाति गोंड, निवासी ग्राम धुममाडांड, पोस्ट गोविंदपुर, थाना चंदौरा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हूं।मै शपथपूर्वक कथन करता हु कि

1. मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 21-04-2025 को हुआ था।

2.जन्म के समय भूलवश उसका नाम आयांश दर्ज हो गया था।

3.परन्तु अब हम अपने पुत्र का सही नाम दिव्यांश करवाना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज के बाद मेरे पुत्र का नाम दिव्यांश ही पढ़ा जाये। यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम/जन्म तिथि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय-सीमा में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर मेरे पुत्र का नाम आयांश के स्थान पर दिव्यांश ही पढ़ा जायेगा।

शपथकर्ता
वंशलाल,
पिता भानमती, जाति गोंड,
निवासी ग्राम धुममाडांड, पोस्ट गोविंदपुर,
थाना चंदौरा, तहसील प्रतापपुर,
जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

सम्पादकीय

सीमा सुरक्षा के साथ सतर्कता भी जरूरी

भारत-पाकिस्तान सीमा पर अमृतसर के दाउके गांव में घुसपैठिए को बीएसएफ द्वारा मार गिराए जाने की घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सीमा सुरक्षा में छोटी-सी चूक भी बड़ी चुनौती का रूप ले सकती है। कंटीली तार के पास संदिग्ध गतिविधि, जवानों की सतर्कता, चेतावनी और उसके बाद हुई फायरिंग पूरी घटना बताती है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों को हर समय सतर्कता बरतनी पड़ती है। सीमा पर यह घटना ऐसे समय हुई है, जब पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से आधुनिक बनाने में जुटा है। रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारत से लगे इलाकों में चीन निर्मित एसएच-15 व्हील्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात किए हैं। इनकी संख्या करीब 250 बताई जा रही है, हालांकि इस तैनाती की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि यह आकलन सही है तो इसे केवल हथियारों की खरीद का मामला मानना उचित नहीं होगा। यह चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते सैन्य एवं रणनीतिक सहयोग का एक और गंभीर संकेत है। एसएच-15 स्वचालित तोप ट्रक चेसिस पर आधारित है और शूट एंड स्कूट क्षमता के कारण गोलीबारी के बाद तेजी से स्थान बदल सकती है। इससे जवाबी गोलाबारी का जोखिम कम होता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी प्रणालियां सीमा के पास तैनात होने पर किसी भी सैन्य संकट में दोनों पक्षों के लिए प्रतिक्रिया का समय घटा सकती हैं। यही वह पहलू है, जिसे भारत को गंभीरता से देखना चाहिए। चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग की कहानी नई नहीं है। चीन के लिए पाकिस्तान एक रणनीतिक साझेदार होने के साथ-साथ उसके रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बाजार भी है, जबकि पाकिस्तान को अपेक्षाकृत कम लागत पर सैन्य आधुनिकीकरण और पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटाने का अवसर मिलता है। भारत के लिए चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसे एक साथ दो सीमाओं पर रणनीतिक परिस्थितियों पर नजर रखनी पड़ती है। पाकिस्तान की बढ़ती आर्टिलरी क्षमता, रॉकेट सिस्टम और अन्य सटीक मारक हथियारों के साथ चीनी तकनीक का मेल भविष्य के किसी संकट में सैन्य गणित को प्रभावित कर सकता है। अमृतसर की घटना इस बड़े परिदृश्य का जमीनी पहलू सामने रखती है। सीमा पर केवल भारी हथियारों की चुनौती नहीं है, बल्कि घुसपैठ, तस्करी, ड्रोन और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए सीमा सुरक्षा को केवल जवानों की संख्या या हथियारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आधुनिक सेंसर, ड्रोन निगरानी, कैमरा नेटवर्क, बेहतर खुफिया तंत्र और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तेज सूचना-साझाकरण को और मजबूत करना होगा। भारत को पाकिस्तान की हर गतिविधि पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी निवारक क्षमता को इतना मजबूत करना होगा कि किसी भी संभावित दुस्साहस की कीमत स्पष्ट हो। साथ ही, संदिग्ध घुसपैठ की घटनाओं में सख्त कार्रवाई के साथ निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच भी जरूरी है। चीन-पाकिस्तान का बढ़ता सैन्य तालमेल भारत के लिए निश्चित रूप से सतर्क रहने का संकेत है, लेकिन इसे अनावश्यक भय का कारण बनाना भी उचित नहीं। भारत की वास्तविक ताकत उसकी तकनीकी क्षमता, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, खुफिया तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया में है। सरहद पर चौकसी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी दूरदर्शी रणनीति भी है। सीमा की सुरक्षा केवल कंटीली तार से नहीं, बल्कि मजबूत निगरानी, आधुनिक तकनीक और हर संभावित खतरे के लिए तैयार रणनीति से सुनिश्चित होगी।

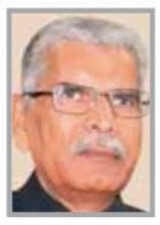

शिक्षा के पंचतत्व

प्रो. रमेश चंद्र कुहाड़

शिक्षा संस्थानों की अभिरक्षा का पुनर्निर्माण

> प्रश्नपत्र लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर उत्पन्न विवादों ने करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के मन में गहरी चिंता उत्पन्न की है। वर्षों की कठोर साधना, अथक परिश्रम और असंख्य सपनों का भविष्य जब कुछ क्षणों में संदेह के घेरे में आ जाता है, तब सबसे अधिक आहत विद्यार्थी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता होती है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक त्रुटि या तकनीकी विफलता का परिणाम नही, शिक्षा व्यवस्था की संरचना, उत्तरदायित्व और संस्थागत स्वायत्तता पर गंभीर पुनर्विचार का आह्वान भी है। इन चुनौतियों का समाधान केवल कठोर कानूनों, दंडात्मक प्रावधानों अथवा आधुनिक तकनीकी निगरानी में नहीं खोजा जा सकता।

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक संपन्नता अथवा तकनीकी प्रगति में नहीं, बल्कि उसकी शिक्षित, जागरूक, नैतिक और उत्तरदायी युवा पीढ़ी में निहित होती है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाज की संस्कृति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करने वाली सबसे प्रभावशाली शक्ति है। इसलिए जब शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं, तब संकट केवल किसी परीक्षा, विश्वविद्यालय अथवा संस्था का नहीं होता; वह राष्ट्र के भविष्य, सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता का संकट बन जाता है।

हाल के वर्षों में प्रश्नपत्र लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर उत्पन्न विवादों ने करोड़ों विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के मन में गहरी चिंता उत्पन्न की है। वर्षों की कठोर साधना, अथक परिश्रम और असंख्य सपनों का भविष्य जब कुछ क्षणों में संदेह के घेरे में आ जाता है, तब सबसे अधिक आहत विद्यार्थी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता होती है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक त्रुटि या तकनीकी विफलता का परिणाम नहीं है; यह शिक्षा व्यवस्था की संरचना, उत्तरदायित्व और संस्थागत स्वायत्तता पर गंभीर पुनर्विचार का आह्वान भी है। इन चुनौतियों का समाधान केवल कठोर कानूनों, दंडात्मक प्रावधानों अथवा आधुनिक तकनीकी निगरानी में नहीं खोजा जा सकता। स्थायी समाधान तभी संभव है, जब शिक्षा की मूल आत्मा, उसकी संस्थागत संरचना और शैक्षणिक उत्तरदायित्व को पुनः सुदृढ़ किया जाए। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पांच आधारभूत तत्व-प्रवेश, पाठ्यक्रम, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम पर आधारित है। यदि इनमें से कोई भी तत्व शिक्षा संस्थानों के नैतिक और शैक्षणिक नेतृत्व से बाहर चला जाता है, तो उत्तरदायित्व का स्वाभाविक क्षरण प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरदायित्व का यह विखंडन अंततः पारदर्शिता को कमजोर करता है और वही परिस्थितियां प्रश्नपत्र लीक, अनियमितताओं तथा जनविश्वास के ह्रास जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न बाहरी एजेंसियों के बीच विभाजित होते जा रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया कोई संस्था संचालित करती है, प्रश्नपत्र किसी अन्य एजेंसी द्वारा तैयार किए जाते हैं, परीक्षा किसी तीसरे तंत्र के माध्यम से आयोजित होती है और परिणाम भी कई स्तरों की बाहरी व्यवस्थाओं पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण कठिन हो जाता है। जब उत्तरदायित्व बिखरता है, तब पारदर्शिता और जवाबदेही भी स्वतः कमजोर पड़ जाती है। परिणामस्वरूप किसी त्रुटि अथवा विफलता की स्थिति में दोष तो दिखाई देता है, परंतु उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। शिक्षा केवल परीक्षा आयोजित करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शोध, संवाद, मूल्यांकन और सतत बौद्धिक विकास के बीच निरंतर चलने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है।

शिक्षक केवल विषय-विशेषज्ञ नहीं होता; वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्माता होता है। यदि प्रवेश से लेकर परिणाम तक की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा

संस्थानों की भूमिका सीमित कर दी जाएगी, तो धीरे-धीरे उनका शैक्षणिक महत्व भी कम होने लगेगा। तब विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल भवन बनकर रह जाएंगे, जबकि शिक्षा का वास्तविक केंद्र उनका बौद्धिक वातावरण, नैतिक संस्कृति और अकादमिक परंपरा होती है। निस्संदेह विद्यार्थियों की सुविधा, समान अवसर और राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक प्रवेश प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसी व्यवस्थाओं ने विद्यार्थियों का समय, श्रम और आर्थिक व्यय कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु अनुभव यह भी दर्शाते हैं कि अनेक विश्वविद्यालयों में अपेक्षित संख्या में विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं।

परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाती हैं और बार-बार ओपन काउंसलिंग आयोजित करनी पड़ती है। यह केवल प्रवेश प्रक्रिया का प्रश्न नहीं, बल्कि संस्थागत उत्तरदायित्व, स्थानीय शैक्षणिक आवश्यकताओं और विश्वविद्यालयों की सक्रिय भूमिका से भी जुड़ा विषय है। अतः आवश्यकता किसी एक छोर पर खड़े होकर केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का समर्थन करने की नहीं, बल्कि संतुलित और उत्तरदायी व्यवस्था विकसित करने की है। यदि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं आवश्यक समझी जाती हैं, तो भी प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरणों, विषय चयन, शैक्षणिक परामर्श और प्रवेश प्रबंधन में विश्वविद्यालयों की भूमिका अधिक सशक्त होनी चाहिए। इससे शिक्षा के प्रथम पंचतत्व, प्रवेश का स्वाभाविक संबंध पुनः शिक्षा संस्थानों से स्थापित होगा। इसी प्रकार यदि सरकार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, सिविल सेवाओं अथवा अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक समझती है तो उनकी शैक्षणिक विश्वसनीयता, गोपनीयता, निष्पक्षता और शुचिता का नेतृत्व शिक्षा संस्थानों तथा अनुभवी शिक्षकों के हाथों में होना चाहिए। आधुनिक तकनीक, सूचना-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां इस प्रक्रिया के आवश्यक सहयोगी अवश्य हों, किंतु परीक्षा की शैक्षणिक आत्मा का केंद्र शिक्षक ही रहना चाहिए। एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली केवल तकनीकी दक्षता से निर्मित नहीं होती। उसके लिए शिक्षकों, प्रशासकों, सूचना-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों तथा सहयोगी कर्मचारियों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। फिर भी उसकी शैक्षणिक विश्वसनीयता का मूल आधार शिक्षक ही होता है। शिक्षक के लिए शिक्षण केवल आजीविका नहीं, बल्कि ज्ञान, चरित्र और समाज के प्रति आजीवन नैतिक उत्तरदायित्व है। यदि हमें प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पुनः स्थापित करनी है और समाज का विश्वास सुदृढ़ करना है, तो शिक्षा के पंचतत्व -प्रवेश, पाठ्यक्रम, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम को पुनः शिक्षा संस्थानों की अभिरक्षा, उत्तरदायित्व और नैतिक नेतृत्व में प्रतिष्ठित करना होगा।

यही शिक्षा की गरिमा, शिक्षक की प्रतिष्ठा और विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है। भारत यदि ज्ञान-आधारित, नवाचारी और विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प रखता है, तो उसे शिक्षा को केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की सर्वोच्च संस्था के रूप में देखना होगा। प्रवेश, पाठ्यक्रम, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम- ये पांचों पंचतत्त्व तभी अपनी पूर्ण सार्थकता प्राप्त करेंगे, जब उनका संचालन उत्तरदायी, स्वायत्त और नैतिक शैक्षणिक नेतृत्व के अंतर्गत होगा। यही शिक्षा की विश्वसनीयता, शिक्षक की गरिमा, विद्यार्थी के भविष्य और राष्ट्र के ज्ञान-आधारित विकास की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है।

(लेखक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मेटा पर सखी

डॉ. मोनिका शर्मा

सुरक्षा-सम्मान से जुड़ी जवाबदेही लेनी होगी

मौजूदा दौर में हर मोर्चे पर डिजिटल होते जीवन में भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स नियमों से परे नहीं हो सकते। विशेषकर नागरिकों और देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाल ही में भारत सरकार ने मेटा के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यही बात स्पष्ट रूप कही है कि देश में काम करने वाले सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा मेटा कंपनी से एआई, डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री और कंटेंट मॉडरेशन पर भी जवाब मांगा गया है। आईटी नियमों को और सख्त करने का प्रस्ताव रखने के साथ ही कई अहम मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा के बाद मेटा ने यह भी स्वीकार किया कि बहुत सारा गैरकानूनी कंटेंट प्रमोट किया गया और खास ऑडियंस के लिए पेड प्रमोशन किए गए। ज्ञात हो कि इन्हीं दिनों फेसबुक और इंस्टाग्राम की मनमानियों पर अमेरिकी अदालत ने भी एक अहम निर्णय दिया है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ और सुरक्षा में गंभीर चूक के बाद मेटा को अरबों रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। यह सख्त निर्णय इस कंपनी द्वारा अपने फायदे के लिए बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक सेहत को पूरी तरह दरकिनार करने के गंभीर आरोपों के बाद आया है गौरतलब है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को भी कुछ समय के लिए हटाने के साथ-साथ बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट, डीपफेक और बहुत सारा पैसा लेकर कुछ खास सामग्री को बढ़ावा देने जैसी खामियों के लिए माफी मांगी है। ज्ञात हो कि जेन जी आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं से की गई अपील वाले वीडियो संदेश मेटा ने हटा दिया था। मोदी की पोस्ट को तकनीकी समस्या (ऑटोमेटेड फ़िल्टर की त्रुटि) को इसका कारण बताकर कुछ देर बाद बहाल कर दिया था। वहीं न्यू मैक्सिको की एक शीर्ष अदालत के बाद अमेरिका में भी मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने सार्वजनिक रूप से गलती मानते हुए प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़ी सामग्री को रोकने में व्यवस्थागत असफलता की बात स्वीकार की है। साथ ही इस लापरवाही के लिए सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल, बात माफी मांगने से कहीं ज्यादा जवाबदेही लेने की है। इसके लिए कड़े नियम भी जरूरी हैं और मेटा कंपनी में दायित्वबोध का भाव भी। हालिया वर्षों में देश में होने वाली राजनीतिक घटनाएं हों या चर्चित चेहरों जुड़ा कंटेन्ट। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री हो या कंटेंट मॉडरेशन अपने फायदे के अनुसार नकारात्मक सामग्री को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सोशल मीडिया कंपनी मेटा को कथित पोर्नोग्राफ़ी और अनुचित आयुवर्ग से संबन्धित सामग्री अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। इसका सीधा सार अर्थ है कि इन प्लेटफॉर्म पर पॉक्सो कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि यह नोटिस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की श्रेणी के तहत आ सकते हैं। ज्ञात हो कि 2025 में भी सोशल मीडिया पर बच्चों के अश्लील वीडियो परोसे जाने को लेकर सरकार ने आपत्ति जताई गई थी। बावजूद इसके ऐसी सामग्री को लेकर लापरवाही जारी है। समझना मुश्किल नहीं कि हमारे देश में ही नहीं, दुनियाभर में एल्गोरिदम का खेल खेलने वाली टेक कंपनी मेटा के सभी मंचों पर मुनाफे की सोच हावी है। विचारणीय है कि हमारे देश में सोशल मीडिया पर परोसी या प्रमोट की जाने वाली सामग्री से कई चिंताएं और चुनौतियां जुड़ी हैं। भारत में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप पर करीब 56 करोड़, यू-ट्यूब पर करीब 50 करोड़, इंस्टाग्राम पर 48 करोड़, फेसबुक पर 40 करोड़, स्नैपचैट पर 21 करोड़ और एक्स पर 2 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। इनमें यूजर्स में युवाओं की संख्या ज्यादा है। अकेले इंस्टाग्राम पर 18 से 24 आयु वर्ग के 64 प्रतिशत युवा हैं। ऐसे में यहां साझा की जा रही सामग्री न केवल देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक-पारिवारिक और राजनीतिक परिवेश की दिशा से जुड़ी है। यही वजह है कि इनके नैतिक दायित्वों को याद दिलाने के साथ ही सख्त नियम बनाने और उनका पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो चला है। मेटा कंपनी के मनमानी रवैए पर केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में उसके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, उन्हें भारतीय कानून का पालन करना ही होगा। साथ ही इस पहलू से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए हर कदम उठाना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जब मन अशांत हो, इष्टदेव के मंत्रों का करें जप

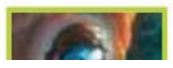

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खद मौत के खिलौने हैं। ये

संकलित

दर्शन

सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

कपड़े की उपयोगिता दिखावे के लिए नहीं

संत कबीर रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। कबीर जी के उपदेश सुनने एक धनी व्यक्ति भी आता था। धनी व्यक्ति कबीर दास जी से बहुत प्रभावित था। एक दिन उस धनी व्यक्ति ने देखा कि कबीर दास जी जो कुर्ता पहनते हैं, वह बहत पराना हो गया और कर्ता बहत ही सामान्य कपडे से बना था।

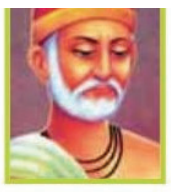

संकलित

प्रेरणा

अगले दिन धनी व्यक्ति एक मूल्यवान कुर्ता लेकर पहुंचा और कबीर दास को उपहार में दे दिया। कुर्ता मखमल से बना था। बाहर की ओर से कुर्ता मखमली था और अंदर की ओर उसमें सामान्य कपड़ा लगा था। धनी व्यक्ति ने सोचा था कि अब कबीर दास जी उसका दिया हुआ कुर्ता पहनेंगे। अगले दिन जब वह व्यक्ति फिर से कबीर दास जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर जी ने उल्टा कुर्ता पहना है। दरअसल, कबीर दास जी के कुर्ते का मलमल वाला हिस्सा अंदर की ओर था और बाहर सामान्य कपड़ा दिख रहा था। उस धनी व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा कि ये आपने क्या किया? आपने तो कुर्ता उल्टा पहना है? सभी लोगों ने भी कबीर दास जी से पूछा कि कुर्ता मूल्यवान है तो आपने इसे उल्टा क्यों पहना है? कबीर जी ने कहा कि ये कुर्ता देखकर मैंने सोचा कि मखमल शरीर को स्पर्श होगा तो शरीर को ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि ये कपड़ा तो शरीर के लिए ही हैं। दिखाने के लिए तो साधारण हिस्सा ही काफी है। दूसरों को हमारे कपड़ों से क्या लेना-देना?

सटाका

आज की पाती

गांव की हर चीज चाहिए लेकिन गांव नहीं चाहिए

यह एक साधारण-सा वाक्य नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय समाज की बदलती मानसिकता का सटीक चित्रण है। हम गांव के शुद्ध दूध की बात करते हैं, देसी घी की प्रशंसा करते हैं, जैविक अनाज खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, गांव के फलों और सब्जियों को स्वास्थ्य का आधार मानते हैं, गांव की संस्कृति, लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक जीवन को अपनी पहचान बताते हैं, लेकिन जब स्वयं गांव में रहने की बात आती है तो अधिकांश लोग उससे दूरी बनाना चाहते हैं। यह विरोधाभास केवल जीवन-शैली का नहीं, बल्कि विकास की हमारी अवधारणा का भी प्रश्न है। भारत को सदियों से गांवों का देश कहा जाता रहा है। आज भी देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव कृषि पर टिकी है और कृषि गांवों के बिना संभव नहीं है। – *धर्मपाल छिकारा, गोहाना*

ट्रेंड

गर्व का पल

भारतीय खेलों के लिए गर्व का पल, जब हमारे युवा एथलीटों ने वैश्विक मंच पर शानदार प्रदर्शन किया ! बसंत का हाई जंप में भारत का पहला मेडल और शाहनवाज का ब्रॉन्ज मेडल, हमारे रक्षा बलों के समर्पण, अनुशासन की मिसाल है।

- **राजनाथ सिंह,** रक्षामंत्री

रोशनी की मशाल

सिस्टम की फैलाई गई अंधेरी फिज़ा के बीच, देश के छात्रों ने अपने डर का सामना किया और रोशनी की मशाल जलाई है। अब समय आ गया है कि बीजेपी-आरएसएस और अडानी के सिस्टम को 'टाटा-बाय-बाय' कहकर खत्म कर दिया जाए।

- **राहुल गांधी,** सांसद, कांग्रेस

'हर घर तिरंगा' अभियान

'हर घर तिरंगा' अभियान हर व्यक्ति तक देशभक्ति की भावना पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। आइए, हम सब उत्साह के साथ इस अभियान से जुड़ें और 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

- **नितिन नवीन,** अध्यक्ष, भाजपा

कानून-व्यवस्था कमजोर

पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं को डराने और उन पर हमला करने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जान-बूझकर कानून-व्यवस्था को कमजोर किया है। जैसे-जैसे मोदी सरकार की लोकप्रियता घट रही है, बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है।

-**अरविंद केजरीवाल,** पूर्व सीएम, नई दिल्ली

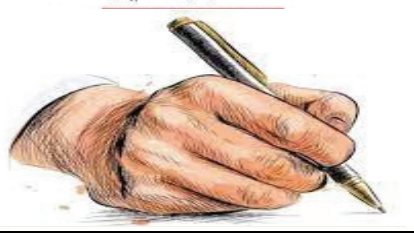

करंट अफेयर

चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका घटी

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को लंबे समय से अपनी उपलब्धियों में से एक बताती रही है। हालांकि, विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि चीन में हाल के वर्षों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका घटी है, खासकर राजनीतिक और नीतिगत नेतृत्व में शीर्ष स्तरों पर। चीन में सत्तारूढ़ सीपीसी ने लैंगिक समानता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर दशकों से माओ जेदोंग के इस प्रसिद्ध नारे को बढ़ावा दिया है कि महिलाएं आधा आसमान थामे हुए हैं। हालांकि, सीपीसी के मुखपत्र 'पीपुल्स डेली' में प्रकाशित विभिन्न लेखों के विश्लेषण पर आधारित एक नये अध्ययन की मानें तो हाल के वर्षों में चीन के सरकारी मीडिया के विमर्श में बदलाव देखने को मिला है और इसमें मुख्य रूप से महिलाओं की घरेलू और पारिवारिक भूमिकाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सीपीसी दशकों से दावा करती आ रही है कि महिलाओं ने समाजवादी आधुनिकीकरण, सुधार और खुलापन लाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि, हांगकांग स्थित दो शोधकर्ताओं के मुताबिक, चीन के सरकारी मीडिया में 1990 के दशक के अंत में महिलाओं के चित्रण में व्यापक बदलाव दिखना शुरू हो गया।

ऑफ बीट

स्मार्ट चश्मे जिंदगी का हिस्सा बन रहे, खत्म होगी निजता

ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर ऐसे चश्मा पहने लोग अच्छी खासी संख्या में दिख जाएंगे जिससे वे आसपास की तस्वीरें और वीडियो बेहद सहजता से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह 'केमार्ट' है, जिसने हाल में सस्ते/"कैमरा वाले चश्मे/ बाजार में उतारे हैं और ये देखते ही देखते बिक गए हैं। ये चश्मे 'केमार्ट' के अपने ब्रांड 'आंको' के हैं जिनकी कीमत महज 89 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, जबकि 'मेटा' और 'रे-बैन' के इसी तरह के उत्पादों की कीमत 337 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से शुरू होती है। 'कैमरा वाले चश्मे' को बड़े उपभोक्ता चलन में बदलने की इस कोशिश की एक कीमत है और वह कीमत चश्मा पहनने वाले की ही नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति की निजता को चुकानी पड़ सकती है। या इनसे रिकॉर्ड की गई तस्वीरें आखिर कौन देख सकता है। यही वजह है कि शुक्रवार को संघीय अटॉर्नी-जनरल मिशेल रोलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के निजता आयुक्त से इस तकनीक की तत्काल समीक्षा करने को कहा। तो क्या मौजूदा निजता कानून तकनीक की इस नयी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? स्मार्ट चश्मे कोई नयी चीज नहीं हैं। गूगल ने 2013 में 'गूगल ग्लास' पेश किया था। उस समय मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई और कई मशहूर हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया।

मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत

विरार ।विरार में काम पर जा रहे 25 वर्षीय युवक की वैतरणा में नए रेलवे ट्रैक को पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।मृतक की पहचान गौरव विलास पाटील (25), निवासी जांभुळपाड़ा, वैतरणा पालघर के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार,गौरव पाटील विरार में काम पर जाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान वैतरणा में नए रेलवे ट्रैक को पार करते समय पालघर से विरार की तरफ जा रही मालगाड़ी ने उन्हें बाईं तरफ से जोरदार टक्कर मार दी।मालगाड़ी की टक्कर लगने के बाद गौरव रेलवे ट्रैक के किनारे जा गिरे। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गए।

I VIRENDRA KUMAR S/O Late GIRISH CHANDRA SHRIVASTAVA Resident of House No 36 G Ambedkar ward Bilaspur road Dist. Hospital, Aspatal parisar Ambikapur Dist. Surguja po. Ambikapur chhattisgarh 497001 Here by declare that have changed myname from Virendra Kumar S/o Late GIRISH CHANDRA SHRIVASTAVA to VIRENDRA KUMAR SHRIVASTAVA in all the Goverment approved Identity proofs to he used for Various purposes in the future

VIRENDRA KUMAR SHRIVASTAVA
ASPATAL PARISAR
Bilaspur road Ambikapur

एससी-एसटी में आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

वर्षों से सामाजिक भेदभाव और अन्याय झेला आर्थिक पिछड़ेपन से तुलना करना ठीक नहीं

केंद्र सरकार ने कहा कि एससी और एसटी को आरक्षण देने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना, ऐतिहासिक भेदभाव को समाप्त करना तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' व्यवस्था लागू करने की मांग का विरोध किया है। सरकार ने कहा कि एससी-एसटी समुदायों ने वर्षों तक सामाजिक भेदभाव और अन्याय झेला है। उनकी स्थिति की तुलना केवल आर्थिक पिछड़ेपन से नहीं की जा सकती। सरकार ने यह भी कहा कि आरक्षण के नियम बदलने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, अदालत के पास नहीं। केंद्र सरकार अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना जवाब दे रही थी।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि एससी और एसटी की पहचान के आधार और ओबीसी की पहचान के आधार अलग-अलग हैं। सरकार ने कहा कि एससी समुदाय छुआछूत जैसी ऐतिहासिक सामाजिक बुराइयों के कारण लंबे समय तक वंचित रहा है। वहीं एसटी समुदाय की पहचान उनकी खास संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। सरकार ने याचिका को 'गलत धारणा पर आधारित और गुण-दोष से रहित' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की है।

आरक्षण के नियम बदलने का अधिकार सिर्फ संसद को

सामाजिक समानता स्थापित करना लक्ष्य

सरकार ने कहा कि ओबीसी की पहचान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। एससी और एसटी को आरक्षण देने का उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना, ऐतिहासिक भेदभाव को समाप्त करना तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।

संपन्न परिवार आरक्षण का लाभ ले रहे: याचिकाकर्ता

याचिका में कहा गया है कि एससी और एसटी वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से संपन्न परिवार आरक्षण का ज्यादातर लाभ ले रहे हैं। इससे आरक्षण का लाभ इन्हीं परिवारों तक सीमित हो रहा है और सबसे अधिक वंचित लोगों को शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। याचिका में सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके लोगों को आरक्षण के लाभ से बाहर करने की मांग की गई है। जो लोग पहले ही सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण देना सकारात्मक भेदभाव के उद्देश्य के विपरीत है। याचिका में सभी आरक्षित श्रेणियों में आय आधारित प्राथमिकता लागू करने की मांग की गई है। याचिका में अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया गया है जिसमें एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई थी। उस पीठ के 7 में से 4 जजों ने अपने फैसले में एससी और एसटी पर भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का सुझाव दिया था।

मणिपुर हिंसा मामला: दो विशेष अदालतें बनेंगी

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और असम की सरकारों समेत अन्य संबंधित अधिकारियों से 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े उन मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें बनाने पर विचार करने को कहा, जिनकी जांच सीबीआई और एनआईए कर रही हैं। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं, उनकी जानकारी एक जगह जुटाई जाए।

विदेश जा सकेंगे अभिषेक

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बेनर्जी को राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेनर्जी की यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि वह एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी मेडिकल जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे।

कावेरी जल विवाद मामला

'सुप्रीम' सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी

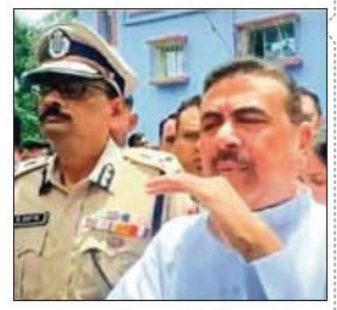

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट इस याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील की दलीलों पर ध्यान दिया। सीजेआई ने कहा, हम इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

शिवसेना (यूबीटी) की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते टली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना (यूबीटी) की उस याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी, जिसमें उसके 6 सांसदों के महाराष्ट्र के उपसीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा अध्यक्ष की ओर से दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद गणपत सावंत की ओर से दाखिल याचिका पर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और अन्य संबंधित पक्षों को अभी तक जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है।

टीएमसी कार्यकर्ता की मौत का मामला

सीएम ने दिए जांच के आदेश परिजनों को 10 लाख की मदद

जांच अधिकारी निलंबित

एजेंसी ▶▶ कोलकाता

पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपये की मदद देने की भी घोषणा की। अधिकारी के साथ भाजपा विधायक अर्जुन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद थे। मृतक के परिवार से मुलाकात के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हालीशहर थाने के प्रभारी निरीक्षक को क्लोज (जिम्मेदारी से हटाना) कर दिया है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी को भी केओट की मौत के मामले में निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस लॉकअप में की पिटाई: पत्नी

कांचरापाड़ा नगरपालिका की पूर्व पार्षद जेनी शर्मा केओट के पति बिरजू केओट को जबरन वसूली और अन्य आरोपों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। शनिवार को उनकी मौत की खबर सामने आई। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस लॉक-अप के अंदर केओट की पिटाई की गई थी और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। इस आरोप पर पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बता दें, एक दिन पहले पूर्व सीएम ममता बेनर्जी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मृतक कार्यकर्ता के हालीशहर स्थित घर पहुंची थीं। वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था। उनके खिलाफ 'चोर' के नारे लगाए गए थे। काफिले पर कीचड़ और चप्पलें भी फेंकी गई थीं।

ममता पर हमले में भाजपा का हाथ नहीं

इस मामले में पूर्व ममता बेनर्जी ने अपने काफिले पर कथित हमले में भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि, सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना में भाजपा की किसी भी भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह विरोध ममता बनर्जी के खिलाफ 'लोगों के गहरे आक्रोश' को दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व सीएम ने 'इतनी चोरी की है', इसलिए उन्हें लोगों से अपने लिए 'चोर' शब्द सुनना पड़ेगा।

दिल्ली-एनसीआर में मानसून मेहरबान, मौसम बना खुशनुमा

कई इलाकों में झमाझम बारिश से बदला मौसम

गर्मी-उमस से मिली राहत

सतर्क रहें लोग

कई इलाकों में जलभराव

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने दिल्ली-एनसीआर के मौसम को खुशनुमा बना दिया है। मानसून की सक्रियता के चलते कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। हालांकि, बारिश ने उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत दी है। अगले 5 दिन तक में हल्की बारिश होगी।

दिल्ली के कनॉट प्लेस का दृश्य

तेज हवाएं चलने की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के गाजियाबाद से सटे कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और मध्यम से भारी बारिश की बहुत अधिक संभावना है।

लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बिजली कड़कने के कारण खुले इलाकों में न निकलने, पेड़ों और होर्डिंग्स से दूर रहने तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाने की अपील की गई है। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

नीमकाथाना में सर्वाधिक बारिश

राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि सीकर और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में सीकर के नीमकाथाना में सर्वाधिक 85 मिलीमीटर बारिश हुई, जो भारी बारिश की श्रेणी में आता है।

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दो और लोगों की मौत के बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है, जबकि सात जिलों में करीब 1.4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

'तीसरी मुंबई' बाहरियों को करेगी आकर्षित

मुंबई ,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को राज्य सरकार पर प्रस्तावित ' तीसरी मुंबई' शहर से जुड़ी विकास योजनाओं को लेकर लोगों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन तो स्थानीय लोग देंगे लेकिन फायदा बाहरी लोग उठायेंगे. 'तीसरी मुंबई' या 'करनाला-साई-चिरनेर (केएससी) न्यू टाउन' एक नियोजित स्मार्ट सिटी होगी, जो तटीय रायगढ़ जिले के 124 गांवों के लगभग 323-334 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई होगी. इस नए शहर को विकसित करने का उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम करना और इलाके में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. ठाकरे ने यहां प्रेसवार्ता में दावा किया कि आम लोगों को 'तीसरी मुंबई'के बारे में सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित शहर में एजुकेशन सिटी, मेडिकल सिटी, स्पोर्ट्स सेंटर, 'डेटा सेंटर', 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर' और अनुसंधान केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी.

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती सीतादेवी आ०/पति चिरंजीलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला सदर रोड़, शीट नम्बर-11 क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4817/22 रकबा 0.007 हे० भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 07/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ०ग०)
रा०मा०/ब-121/2025-26
ग्राम-कछार, तहसील पत्थलगांव
ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम पंचायत कछार को सूचित किया जाता है, कि आवेदक शंकर यादव पिता डिलेश्वर यादव, जाति महकुल, निवासी कछार तहसील पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०) व्दारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पुत्र चुडामणी यादव का ग्राम कछार में जन्म दिनांक 23/04/2002 को हुआ है। जिसका नाम ग्राम पंचायत कछार के जन्म पंजी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, पंचनामा, कलेक्टर प्रतिलिपि शाखा जशपुर, व अंकसूची की छाया प्रति संलग्न है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर आपत्ति या दावा हो तो वह स्वयं अथवा मान्य अधिवक्ता अथवा वैध अभिकर्ता के मय दस्तावेज दिनांक 05/08/2026 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि पश्चात्प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 20/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार
एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी
पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ०ग०)

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती सीता देवी आ०/पति चिरंजीलाल अग्रवाल जाति अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया निवासी अग्रसेन वार्ड है कि मोहल्ला सदर रोड़, शीट नम्बर-11क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4817/53 रकबा 431 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 06/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका कैलाश चंद अग्रवाल आ०/पति चिरंजीलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला अस्पताल रोड, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2810/1, 2823/4 रकबा 0.02, 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 07/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आर्वेदिका श्रीमती शशिकला अग्रवाल आ०/ पति ज्ञानेश्वर अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०म० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला बाबूपारा, शीट नम्बर 9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/38 रकवा 1100 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-28
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका। सतीश कुमार दुबे आ०/पति स्व० गिरिवर प्रसाद दुबे जाति ब्राम्हण, निवासी रामनुजगंज रोड़, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला बांक रोड़, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2031/24 रकबा 5000 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 19/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 04/08*2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगॉव तहसील भटगॉव
ईश्तहार
रा.प्र.क्र. ब 121/ 2025- 026

आम जनता ग्राम लक्ष्मीपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक गुर्जर सिंह आ. स्व. घूरन सिंह जाति गोड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील भटगांव जिला सूरजपुर द्वारा अपने बड़े पिता हीरा सिंह का मृत्यु दिनांक 14. 08.1990 को मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने बड़े पिता का प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह दिनांक 12/08/026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात्प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। आज दिनांक 23/07/026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०
रा०प्र०क० / अ-6/2025 26
ईश्तहार

एत्तद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका फुलकुवंर पति स्व. सहदेव, निवासी ग्राम अजिरमा, थाना तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा ग्राम अजिरमा स्थित भूमि खसरा नंबर 830/1 रकबा 0.320 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखो में वर्तमान मृत खातेदार स्व० सहदेव आ. स्व. बुधराम उर्फ करलू का नाम विलोपित कराते हुए उनके विधिक वारिशों के नाम पर फौती दर्ज कराने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/08/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 11/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेद्रिका श्रीमती सीता देवी आ०/पति चिरंजीलाल अग्रवाल जाति अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया निवासी अग्रसेन वार्ड है कि मोहल्ला सदर रोड़, शीट नम्बर-11क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4817/10 रकबा 0.01 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 06/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/अ-20(3)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक हरी राम अग्रवाल आ० स्व० चन्द्रभान अग्रवाल, निवासी ब्रम्ह रोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर-02 मोहल्ला राममंदिर मैदान, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 3196/4813/15 रकबा 14' X12.5' = 175 वर्गफीट भूमि को अनावेदिकागण / केता- पूजा सेठिया पत्नी महावीर सेठिया, रानू सेठिया पत्नी मदन सेठिया, दोनों निवासी अस्तबल के पीछे अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा प्रतिलिपि, शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ०ग०)
रा०मा०क०/ब-121/2025-26
ग्राम-कछार, तहसील पत्थलगांव
ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम पंचायत कछार को सूचित किया जाता है, कि आवेदक खैमासागर यादव पिता त्रिलोचन यादव, जाति महकुल, निवासी कछार, तहसील पत्थलगाव, जिला-जशपुर (छ०ग०) व्दारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पुत्र अजय कुमार यादव का ग्राम कछार में जन्म दिनांक 17/03/2003 को हुआ है। जिसका नाम ग्राम कछार के जन्म पंजी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र. पंचनामा, कलेक्टर प्रतिलिपि शाखा जशपुर, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र व अंकसूची की छाया प्रति संलग्न है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर आपत्ति या दावा हो तो वह स्वयं अथवा मान्य अधिवक्ता अथवा वैध अभिकर्ता के मय दस्तावेज दिनांक 05/08/2026 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 20/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार
एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी
पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ०ग०)

हमर छत्तीसगढ़ के पहिली लोक परब

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हरेली तिहार

के गाड़ा-गाड़ा बधाई

12 अगस्त 2026

कृषकों का आर्थिक सशक्तीकरण

- ढाई वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में **₹1.50 लाख करोड़** से अधिक अंतरित
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि : 25 लाख** से अधिक किसानों को **₹11,277 करोड़** का भुगतान

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

- भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष **₹10,000** की आर्थिक सहायता

कृषि का आधुनिकीकरण

- जीएसटी 2.0 लागू होने से **कृषि उपकरण हुए सस्ते**

कृषक उन्नति योजना

- **₹3,100 प्रति क्विंटल** की दर से प्रति एकड़ **21 क्विंटल** धान खरीदी

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन

- धान के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों की खेती पर प्रति एकड़ **₹15,000** की आदान सहायता

आसान ऋण सुविधा

- खाद- बीज की खरीदी के लिए **ब्याज मुक्त ऋण**

हरियर धरती, खुशहाल किसान
समृद्धि और जनकल्याण, सुशासन की पहचान

आर.ओ. नं.-48731/27

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

हर घर तिरंगा अभियान, निकली भव्य जागरूकता रैली

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी-बिहारपुर। हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर मंगलवार को क्षेत्र में जागरूकता रैली निकली गई। रैली में शासकीय नवीन महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक, बिहारपुर के शिक्षक तिवारी, मनहर, शिव बरन गुप्ता, पासवान सहित अन्य शिक्षककगण एवं छात्र शामिल हुए। वहीं शासकीय आयुर्वेद विभाग, बिहारपुर के अधिकारी डॉ. आशीष कुमार शर्मा एवं योगेश कुमार पटेल का भी सहयोग प्राप्त हुआ।

रैली के माध्यम से क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जनजागरूकता अभियान चलाते हुए 'हर घर तिरंगा' के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना देखने को मिली। रैली में अधिकारी कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की।

नर्मदेश्वर महादेव के जलाभिषेक हेतु 16 को जमड़ी रवाना होंगे शिवभक्त

भव्य कांवड़ पद यात्रा की तैयारी में जुटे समिति के सदस्य

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के पावन अवसर पर नर्मदेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए 16 अगस्त को कांवरियों का जत्था जमड़ी धाम के लिए रवाना होगा। प्रात:6 बजे पावन पुण्य रेणुका नदी के छठ घाट स्थित तट से जल भरकर शिव भक्त कांवरियों का जत्था सूरजपुर से करीब 25 किमी की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक जमड़ी धाम के लिए रवाना होगा। श्रावण मास की नागपंचमी के एक दिन पूर्व होने वाली इस कांवर पदयात्रा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है जो अब पुर्णता की ओर है। प्रतिवर्ष मां दुर्गे स्वाभिमान युवा कल्याण समिति के द्वारा यात्रा का आयोजन किया जाता है। जिसके लिए समिति के सदस्यों ने जमड़ी के साथ सम्पूर्ण रास्ते की व्यवस्था सहित छठ घाट में व्यापक तैयारियां की हैं। 16 अगस्त को प्रात: 6 बजे छठ घाट से कांवड़ में जल भरकर जमड़ी धाम रवाना होने वाले शिव भक्तों के लिए पूरे रास्ते भर जल-पान व भोजन की व्यवस्था की गई है।

इन्होंने की है इन स्थानों पर जलपान की व्यवस्था

हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी सहयोग करने वाले में महंगवा में बजरंग राजवाड़े एवम साथी, परी आत्मा साहू व साथी, परी अग्रवाल परिवार, उचड़ीह दीपक साहू एवं साथी, बसदई चौकी के तरफ से,करकोटी रजनीश पांडे व साथी, मंदिर के पास शाम को नाश्ता अमरदीप सोनी, मंदिर में सुबह का नाश्ता दिनेश गुप्ता, प्रसाद मुकेश साहू, रात्रि में भक्तो के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था जिंदिया परिवार सूरजपुर के ओर से की गई है।

आकर्षक झांकियो के साथ होगा जगराते का आयोजन

कावड़ यात्रा के साथ मध्यप्रदेश से आए झांकी और प्रसिद्ध गायकों के द्वारा विशाल शोभायात्रा किया जाएगा साथ ही रात्रि जमड़ी धाम में भोलेनाथ के विशाल जगराते का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। जिसमे छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायक विवेक शर्मा, मशहूर भोजपुरी गायक पियूष राज, अविनाश पूरी, अंजली गंगवाल, लव मि इंडिया फेम स्तुति जायसवाल इन सभी कलाकारों को एकत्रित कर मां बागेश्वरी जागरण मंच के द्वारा भजनों की अमृत वर्षा और मध्यप्रदेश से आए अद्भुत झांकियों के साथ पूरी रात भोलेनाथ की अलख जगायेंगे।

2010 में प्रारम्भ हुई थी कांवड़ पद यात्रा की परंपरा

जमड़ी धाम कांवड़ पदयात्रा का आयोजन विगत 17 वर्ष पूर्व 2010 में प्रारंभ हुई थी। मां दुर्गे स्वाभिमान युवा कल्याण समिति के युवाओं के द्वारा जमड़ी धाम तक की लगभग 25 किमी की यात्रा को पूर्ण कर एक परंपरा की शुरूआत की थी। महज कुछ लोगों से शुरू हुई यह यात्रा अब हजारों की संख्या में तब्दील हो गई है। इस कांवड़ यात्रा में सूरजपुर शहर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के जयघोष के साथ बोल बम का नारा लगाते हुए कि इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं।

जिले के आदि सेवा केन्द्रों में 13 से 15 तक लगेंगे जन सुनवाई शिविर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के समस्त आदि सेवा केन्द्रों में 13 से 15 अगस्त तक जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जनपद पंचायतों के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा जिले के सभी संबंधित विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुपालन में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सभी आदि सेवा केन्द्रों में निर्धारित तिथियों पर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे, वहीं संबंधित विभाग प्रमुख इन शिविरों में अपने विभाग के ग्रामीण स्तर के अमले की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, ताकि ग्रामीणों को मौके पर ही योजनाओं की जानकारी और लाभ मिल सके। शिविरों के आयोजन में आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा बैंकिंग/सीएससी सहित अन्य विभागों के जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर संचालित आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत सूरजपुर जिले के 6 विकासखण्डों के 284 जनजाति बाहुल्य ग्रामों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आदि सेवा केन्द्रों और आदि कर्मयोगी वालिंटियर्स के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक शासकीय सेवा वितरण को सुदृढ़ करना है। ग्राम स्तरीय इन केन्द्रों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत पात्रता संबंधी सुविधा, शिकायत निवारण, शासकीय योजनाओं के समन्वय और सामुदायिक सहभागिता के स्थायी मंच के रूप में विकसित किया गया है, जबकि प्रशिक्षित स्थानीय वालिंटियर्स जागरूकता सृजन, नागरिक सुविधा विस्तार, डिजिटल दस्तावेजीकरण तथा शिकायतों के अनुवर्ती कार्य में सहयोग करते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ आयोजित हो रहे इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का पंजीयन एवं निराकरण, पात्र हितग्राहियों के आवेदनों की मौके पर पूर्ति, कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता तथा प्राथमिकता वाले जरूरतमंद परिवारों की पहचान का कार्य किया जाएगा।

जिपं सामान्य सभा में समन्वय और जवाबदेही पर दिया गया जोर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला पंचायत सभागार में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा की अध्यक्षता तथा जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र पाटले की उपस्थिति में संपन्न हुई। अध्यक्ष ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सभी का पहला कर्तव्य है और इसके लिए प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के मध्य सशक्त समन्वय आवश्यक है। उन्होंने प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर देते हुए उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसी बैठकें नियमित रूप से आयोजित होंगी, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जा सके। इस दौरान सीईओ श्री पाटले ने जिले के विकास के लिए तैयार कार्ययोजना प्रस्तुत की। बैठक में विभागवार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्रमवार समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मौसमी बीमारियों की रोकथाम, दवाओं की उपलब्धता तथा अन्य स्वास्थ्यगत विषयों पर चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों व भवनों की प्रगति, छात्रावासों में अधीक्षकों की व्यवस्था, सीपेज तथा मरम्मत कार्य एवं शालाओं में शौचालय निर्माण की विस्तृत जानकारी ली गई। क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा के आधार पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूती देने की दृष्टि से कई दूरगामी निर्णय भी लिए गए।बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती रेखालाल राजवाड़े, जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सिंह, जिला पंचायत सदस्य लोकेश पैकरा, नरेंद्र यादव, श्रीमती किरण सिंह केराम, श्रीमती कुसुम सत्यनारायण सिंह, बाबूलाल सिंह मरापो, अखिलेश प्रताप सिंह, अनुज कुमार राजवाड़े, सुरेश कुमार आयाम सहित अन्य जिला पंचायत एवं जनपद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आदिवासी विरोधी मानसिकता से काम कर रही भाजपा : अमरजीत

विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी आयोजन नहीं होने से कांग्रेस हमलावर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में शासकीय स्तर पर आयोजन नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नौ अगस्त को पूरी दुनिया में आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया, लेकिन भाजपा के किसी नेता, आदिवासी नेता, यहां तक कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की ओर से भी आदिवासी समाज को बधाई संदेश नहीं दिया गया। भगत ने कहा कि वर्ष 2023 से पहले भाजपा के नेता भी विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद

इस दिवस को शासकीय स्तर पर मनाने से परहेज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस आदिवासियों की स्वतंत्र संस्कृति और अस्मिता को स्वीकार नहीं करना चाहती तथा उन्हें 'वनवासी' की पहचान तक सीमित करना चाहती है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति और सभ्यता को दुनिया के सामने रखने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की करीब 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समाज की है। प्रदेश की पहचान आदिवासी संस्कृति के बिना अधूरी है। बस्तर से लेकर सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोरबा, जशपुर, बलरामपुर और गरियाबंद तक आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति, परंपरा और संघर्ष से प्रदेश की पहचान बनाई है। इसके बावजूद आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते सरकारी स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाना समाज का अपमान है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपनी अस्मिता, अधिकार और जल-ल जंगल-जमीन के अधिकार से कोई समझौता नहीं करेगा। भाजपा और आरएसएस भले ही विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करें, लेकिन आदिवासी समाज इसे गर्व के साथ मनाता रहा है और आगे भी मनाता रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी दिवस आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकार, संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा विषय है। आदिवासी समाज की परंपराओं और अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। कांग्रेस जल, जंगल और जमीन के अधिकार तथा आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। इस दौरान कांग्रेस महामंत्री संजय डोशी, उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन, इस्माईल खान, जीएस मिश्रा, प्रवेश गोयल, विद्यासागर सिंह, विनय मिश्रा, त्रिभुवन सिंह, वेदप्रकाश मिश्रा, सुनील सारथी, संतोष पावले, राजपाल कसेरा, समीर सिंह, सुनील प्रजापति,बअविनाश साहू, लिवनेश सिंह और परमेश्वर राजवाड़े सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायालय नायब तहसीलदार, बतौली जिला सरगुजा (छ०ग०)

रा.प्र.क/अ–6/25–26
ग्राम– तेलईधार, प० ह० नं० 19

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छ०ग० राज्य वक्फ बोर्ड के पदेन सचिव द्वारा ग्राम तेलईधार तहसील बतौली स्थित वाद भूमि ख0नं0 786 रकबा 0.271 व ख0नं0 2458/1 में से रकबा 0.198 हे० भूमि मदरसा (खैरूल अनवांर के निर्माण हेतु खुली भूमि) के लिए सुरक्षित के वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 5 (3) (I) (II) तथा 37(2) (3) के अनुसार वक्फ संपत्ति के क्षेत्राधिकार कार्यालय (नामान्तरण अधिकारी) को औकाफ की वक्फ संपत्ति का रजिस्टर (एवं राजपत्र) का विवरण भू–अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि के उद्देश्य से छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड अस्तान्तरणीय दर्ज करने हेतु मय आवे. दन, बी–1 की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी संस्था या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी तिथि दिनांक 14/08/2026 के पूर्व आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि उपरान्त प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आज दिनांक 28/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुदा द्वारा जारी।

नायब तहसीलदार
बतौली, सरगुजा

मनरेगा पर शोध के लिए शासकीय व्याख्याता मुकेश उपाध्याय को मिली पीएचडी की उपाधी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। सरगुजा संभाग में शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सखौली के व्याख्याता मुकेश उपाध्याय व बलरामपुर जिले के निवासी ने वाणिज्य एवं प्रबंधन के अंतर्गत आईएसबीएम यूनिवर्सिटी, गरियाबंद (छत्तीसगढ़) से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदान विषय पर अपना शोध पूर्ण कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है।डॉ मुकेश उपाध्याय मूलत वाड्रफनगर विकाशखंड के ग्राम नवली सरना के निवासी है उनके पिता भी सेवा निवृत प्रधान पाठक है।

उनके शोध में मनरेगा के तहत ग्रामीण हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ, रोजगार एवं आय के अवसर तथा योजना का ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। शोध को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नीति निर्धारण के लिहाज से महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया है। डॉ. मुकेश उपाध्याय ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने शोध निर्देशक डॉ. अमित वर्मा, माता-पिता सहित हॉली क्रॉस विमेंस कॉलेज के वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. विनोद गर्ग को दिया है।उनकी सफलता पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा, प्राचार्य श्रीमती नेली अनिता कुजूर, शिक्षक- शिक्षिकाओं, सहकर्मियों, विद्यार्थियों, परिजनों, मित्रों, ग्रामीणों एवं शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

संवैधानिक एवं पारंपरिक अधिकारों के प्रति जागरुक हो रहा समाज : पोया

विश्व आदिवासी दिवस पर रामानुजनगर में निकली रैली, हुई जनसभा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। विश्व आदिवासी दिवस पखवाड़े के तहत मंगलवार को रामानुजनगर में सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग एवं आदिवासी समाज द्वारा रैली और जनसभा का आयोजन किया गया। विभिन्न मार्गों से निकली रैली स्टेडियम ग्राउंड पहुंची, जहां आदिवासी समाज के सैकड़ों युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज की विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सोशल एक्टिविस्ट एवं सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के जिला अध्यक्ष बीपीएस पोया ने आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, जल जंगल जमीन, संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से शुभकामना संदेश नहीं आने के विषय पर समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दीं, जबकि प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी की ओर से सार्वजनिक बधाई संदेश नहीं दिया गया। पोया ने प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद प्रेमनगर विधानसभा सीट सामान्य सीट हो गई, जबकि इससे पहले यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से प्रभावी पहल की आवश्यकता बताई।

उन्होंने सरगुजा संभाग में आदिवासी भूमि की खरीद-बिक्री, भूमि संरक्षण, आदिवासी महिलाओं एवं नाबालिगों से जुड़े अपराध, रोजगार के लिए युवाओं के पलायन तथा पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने जैसे मुद्दों पर प्रशासन से गंभीरता से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष सभी को समानता मिलनी चाहिए तथा गरीब और आदिवासी पीड़ितों के मामलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

बीपीएस पोया ने कहा कि आदिवासी समाज का युवा अब अपने संवैधानिक एवं पारंपरिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है। समाज लोकतांत्रिक तरीके से कलम और जनआंदोलन के माध्यम से अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगने वाले समुदायों को केवल आरक्षण तक सीमित न रहकर आदिवासी संस्कृति, प्रकृति, जल-जंगल-जमीन और पारंपरिक जीवन-पद्धति के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश सिंह मरकाम, बलरामपुर ने समान नागरिक संहिता से संबंधित संभावित प्रक्रिया को लेकर आदिवासी समाज की चिंताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के संवैधानिक एवं पारंपरिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी नई व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आदिवासी हितों से जुड़े विषयों पर सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। पारंपरिक गीत-संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़ाया और आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग रक्सेल अंबिकापुर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक मरकाम वाड्रफनगर, कार्यक्रम संयोजक इंद्रजीत सिंह युवा, सोनू शाम, दीपक सोनवानी, सोखन सिंह, नरेंद्र मरकाम, अनुक, प्रमोद सिंह मरावी, युगेश सिंह टेकाम, आयुष सिंह पोर्ते, प्रतिमा सिंह पावले, रोहित सिंह टेकाम, सोनू सिंह मरावी, रामविचार नेताम, बलवत सिंह मरावी, हिरालाल सिंह करियाम, शिवप्रसाद सिंह अरमो, रामचंद्र सोरी एवं सत्या सिंह श्याम सहित युवा संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सेवा किटी ने स्वतंत्र भारत में युवा आक्रोश पर आयोजित की निबंध प्रतियोगिता

अंबिकापुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में सेवा किटी समूह द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली निबंध प्रतियोगिता इस वर्ष भी संपन्न हुई। विषय था-स्वतंत्र भारत में युवा आक्रोश के कारण और निदान।

कार्यक्रम में हाईस्कूल एवं महाविद्यालय के लगभग 75 प्रतिभागी शामिल हुए। शासकीय कन्या शाला, हायर सेकेंड्री स्कूल पुलिस लाइन, मल्टीपरपज स्कूल, होलीक्रॉस, शिशु मंदिर, विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, सरगवां के अलावा राजीव

गांधी पीजी कॉलेज, राजमोहनी देवी कन्या महाविद्यालय और हरकेवल दास बी.एड. कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने अपने अमूल्य विचार निबंध लेखन के माध्यम से रखे। इस अवसर पर संयोजिका वंदना दत्ता सहित आयोजन समिति की सदस्य मधु चौदहा, दीपमाला सिंह, सुनीता दास, अंजना परिहार, स्मिता तिवारी, पूजा दुबे और कल्पना मिश्रा उपस्थित थीं। सेवा किटी समूह ने बताया कि स्वाधीनता दिवस के उपरांत विजेताओं को पुरस्कार एवं सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। समूह का उद्देश्य युवाओं को देश की समस्याओं पर सोचने और समाधान सुझाने के लिए मंच देना है।

श्री डी. के सोनी

छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष - हिल द वर्ल्ड फाउंडेशन, दिल्ली
छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष - राष्ट्रीय मानव अधिकार संसाधन विकास संस्था, नागपुर
छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष - अखिल भारतीय स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन
अध्यक्ष - सरगुजा सोसाइटी फॉर जस्टिस, अम्बिकापुर
संरक्षक - सरगुजा सीने आर्ट एसोसिएशन, अम्बिकापुर
सदस्य - नेशनल फेडरेशन ऑफ़ सोसाइटी फॉर फ़ास्ट जस्टिस, दिल्ली
सदस्य - सरगुजा स्वर्णकार समाज

पारिवारिक जानकारी
पिता: **स्व. रामजी प्रसाद सोनी**
माता: **श्रीमती किरोधा देवी**
पत्नी: **श्रीमती रजनी सोनी**
जन्मदिन: **12 अगस्त 1976**

DK MOVIE COMING SOON

शिक्षा: **बीए, एलएलबी, पी.एच.डी.**
डॉक्टर ऑफ फिलोस्पी
कार्यक्षेत्र: **सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ वकालत, सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता।**

पुत्र: **स्पर्श सर्राफ**
इंटरनेशनल स्पीड बॉल खिलाड़ी हैं जो कई मेडल जीतकर सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किये हैं।

पुत्र: **शौर्य सर्राफ**
फेंसिंग (तलवारबाजी) का नेशनल खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा भी कई मेडल जीतकर सरगुजा का नाम रोशन किया गया है।
शौर्य सर्राफ का जन्मदिन 13 अगस्त को है।

डॉ. डी.के. सोनी जी
को जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनायें

कर्म को ही आराधना मानकर समर्पण की पेश की बड़ी मिसाल
भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्रम्हास्त्र - डॉ. डी.के.

एक शख्स जिसने भ्रष्टाचार को रोकने आवाज़ उठाई, एक शख्स जिसने गांव की गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों और न्यायालय तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कोई इन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से जानता है तो कोई इन्हें समाजसेवी कहता है। कई नामों से जाने जानेवाले इस शख्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी है कि लाखों रुपये का अर्थदंड भ्रष्टाचारियों को भरना पड़ा है। लोगों को मनरेगा की लंबित मजदूरी से लेकर ठेकेदारों द्वारा रोके गये रकम तक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नेक कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। इस शख्स ने अपनी एक अलग पहचान प्रदेश में कायम की है। पेशे से अधिवक्ता और अम्बिकापुर निवासी दिनेश सोनी अर्थात डॉ. डी के सोनी से कौन वाकिफ नहीं है। जिनके नाम से ही भ्रष्टाचारियों कि नींद हराम हो जाती है।

डॉ. डी.के. सोनी जो की छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिले सरगुजा के अंबिकापुर में रहते हैं और वकालत के साथ-साथ आरटीआई कानून के माध्यम से आदिवासियों के हित के मुद्दो को हमेशा उठाया है, भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेता के विरुद्ध कई मामलों में कार्यवाही कराते देखे गए हैं। मनरेगा योजना में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी अधिकारियों से इन्होंने कराई है। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं सहित अन्य योजनाओं व भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। इस के आलावा ग्राम न्यायालय की स्थापना कराने और घर पर न्याय की परिकल्पना को पूरा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई है, इसके अलावा सरगुजा के घने जंगलों जिसमे हसदेव अरण्य आता है उसे कोल उत्खनन के लिए काटने की अनुमति दे दी गई जिसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के खिलाफ भी जनहित याचिका लगाया है। जल, जंगल और आदिवासियों की जमीन को बचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह समय समय पर और भी जनहित के कार्यों में खेल संघों को आगे बढ़ाने में इनकी विशेष रुचि है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर वनांचल क्षेत्र अंबिकापुर से आने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. डी.के सोनी जी जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं उनके द्वारा हमेशा से भ्रष्टाचार, न्याय में देरी एवं विभिन्न क्षेत्र में समाज सेवा हेतु अनेक उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं जिसके लिए उन्हें समय-समय पर सम्मानित भी किया गया है।

डॉ. डी.के सोनी आम जन के लिए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम और शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु अपनी संस्था सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के माध्यम से हमेशा जमीनी एवं कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं इसी कड़ी में उन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन के लिए भी एक लंबी लड़ाई जारी रखी हुई है।

सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट, समाजसेवी, अधिवक्ता डॉ. डी.के सोनी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में उपभोक्ता हितों के संरक्षण और पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने हेतु उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की नियुक्ति, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा ई फाइलिंग जैसे बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन सहित आरटीआई के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इंटरविनर बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं।

सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष एवं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. डी.के सोनी जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 में व्याप्त त्रुटि जैसे जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों में अनुभव में अंतर को सुधार हेतु जिससे वरिष्ठ पद अध्यक्ष के लिए अधिवक्ता का केवल 7 वर्ष का अनुभव होना और कनिष्ठ पद सदस्य के लिए 15 वर्ष के अनुभव असंतुलित को सुधार करना, नियुक्तियों में राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्णता खत्म करना, चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूरा कर लिए जाने के बाद नियुक्ति प्रदान करने हेतु समय सीमा तय करना, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व सदस्यों के कार्यानुभव को भी अनुभव में शामिल करना, सुनवाई की पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता को शामिल करना तथा मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान मध्यस्थता की व्यवस्था में सुधार कर कंपनियों द्वारा अपने मध्यस्थ पैनल को विवाद उत्पन्न होने वाले राज्य में होने की अनिवार्यता लागू करना जैसे कई और सुधार हेतु जमीनी और कानूनी लड़ाई के साथ साथ संबंधित विभाग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भी उक्त त्रुटियों और की जाने वाली सुधारों से अवगत कराया गया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ 20 वर्षों का निर्णायक संघर्ष

अधिवक्ता डॉ. डी. के. सोनी का व्यक्तित्व असाधारण है, जिन्होंने पिछले 20 वर्षो से अपना जीवन पारदर्शिता और न्याय की लड़ाई को समर्पित कर दिया है...

- **कानूनी हथियार** : 4000 से अधिक आरटीआई आवेदन दाखिल किए और 18 से अधिक जनहित याचिकाएँ दायर की हैं।
- **ऐतिहासिक मामले** : न्याय सुनिश्चित करने के लिए वह 3 ऐतिहासिक मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए।
- **गरीबों के लिए पैरवी** : उन्होंने गरीब मजदूरों, आदिवासियों और वंचित तबकों के लिए निःशुल्क सैकड़ों मुकदमों की पैरवी की है, जिसमें पहाड़ी कोरबा जैसे विशेष आदिवासी समूहों को न्याय दिलाना शामिल है।
- **प्रमुख अभियान** : उन्होंने वन संरक्षण को बढ़ावा दिया, मनरेगा घोटाले का सफलतापुर्वक पर्दाफाश किया, और भ्रष्टाचार व अवैध भूमि अधिग्रहण के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया।
- **न्यायिक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका** : गरीबो और जरुरतमंदों को शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की स्थापना की। डॉ. डी.के. सोनी स्वर्णकार समाज की राष्ट्रीय संस्था स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरगुजा स्वर्णकार समाज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

- **चुनौतियां और समर्पण**
  बतौर अधिवक्ता, डॉ. डी. के. सोनी ने अधिकारियों और यहां तक कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकियों, झूठे मुकदमों और गलत आरोप जैसी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा वर्तमान में भी करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते से हटना स्वीकार नहीं किया।

- **प्रेरणादायी जीवन पर बनी फिल्म**
  उनकी इस संघर्षयात्रा को जल्द ही हिन्दी फिल्म के रुप में बड़े पर्दे पर देखा जा सकेगा। उन्हें इससे पहले 'पृथ्वी रत्न' और 'ग्लोबल आइकन' समेत 51 अलग-अलग मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है, और बागेश्वर धाम के अलावा कई राज्यों के राज्यपाल एवं केन्द्रीय मंत्री तथा विदेशों में भी सम्मान प्रदान किया गया ।

विनीत : समस्त मित्रगण एवं शुभेच्छु, जिला - सरगुजा

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर